हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

25 फरवरी, 1987

खण्ड–1 अंक 3

अधिकृत विवरण

विशय–सूची

बुधवार, 25 फरवरी, 1987

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(3)1
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(3)11
राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(3)14
राज्यपाल के अभिभाशण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर मतदान	(3)49
वर्श 1981–82 और 1982–83 की ऐक्सैस डिमांड्ज ओवर ग्रांटस एण्ड ऐप्रोप्रिए ान पर चर्चा तथा मतदान	(7)49
वर्श 1986–87 के सप्लीमैंटरी ऐस्टीमेट्स (दूसरी किस्त) पर चर्चा तथा मतदान	
(1) राज्य के राजस्वो पर प्रभारित अनुमानो पर चर्चा	(3)57
(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगो पर चर्चा तथा मतदान	(3)57

हरियाणा विधान सभा

बुधवार 25 फरवरी, 1987

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ में प्रातः 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज़ अब क्वै चनंज होंगे।

Reduction in rate of penalty for late payment of insttalments to Haryana Housing Board

***1228. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state-

(a) whether any penalty is charged from the allottees of the houses of the Haryana Housing Board on account of belated payment of instalments by such allottees;

(b) if so, the extent thereof; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to reduce the existing rate of such penalty, if any, being imposed and, if so, the time by which such a proposal is likely to materialize?

Ministe of State for Local Government (Shri Lachhman Dass Arora):

(a) Yes.

(b) if any amount due is not paid by any person, a penalty under secion 53-A of the Housing Board Haryana Act, 1971 not exceeding 25% of the amount due can be imposed upon him after giving such person an opportunity of being heard.

(c) There is no proposal under consideration of the Government to reduce the existing rate of penalty.

सेठ राम दास धमीजाः स्पीकर साहब, अम्बाला कैंट में हाउसिंग बोर्ड की एक कॉलोनी है। इसी तरह से सारे हरियाणा में भी ये कालोनीज है। अम्बाला में इन्होने एक कमरे वाले सात सौ मकान अलाट किए हैं जिनकी एक महीने की किस्त 205 रुपए है। इस हिसाब से साल की किस्त 2460 रुपए बनती है। अगर कोई किसी वजह से साल की किस्त नही दे पाता तो उस पर बहुत ज्यादा जुर्माना लगता है। एक केस में इन्होने 2460 रुपए पर 8652 रुपए जुर्माना लगाया है। इस प्रकार से टोटल किस्त 11000 रुपए के करीब बन जाती है। क्या बीस सूत्री प्रोग्राम के होते हुए ऐसा होना चाहिए?

श्री लछमन दास अरोडाः स्पीकर साहब, इनका यह कहना कि 8652 रुपए पैनल्टी के लग जाते हैं, यह बात गलत है। इसमें ऐस्टेट मैनेजर की डिस्कि ान होती है, वह 1 प्रति ात से 25 प्रति ात तक पैनल्टी लगा सकता है। पहले इंस्टालमैंट और पैनल्टी दोनो पर इन्ट्रैस्ट पडता था लेकिन 1984 में इसमें कुछ

अमैडमैंट करके हमने पैनल्टी पर इन्ट्रैस्ट लगाना बन्द कर दिया है।

सेठ राम दास धमीजाः मेरे पास 1986 के नोटिस है जो लोगो को दिए गए है। मेरे पास हर महीने की फिगर्ज़ है। अगर कोई किसी मजबूरी की वजह से एक साल किस्त जमा न करवा सके तो उस पर इतनी पैनल्टी नही डालनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः धमीजा साहब, कुछ अफसर ऐसे होते है जो खु ाामद चाहते हैं। मेरे को भी 50 रुपए से 2500 करके भेज दिए थे।

श्री लछमन दास अरोडाः स्पीकर साहब, अगर मिनिमम पैनल्टी एक परसैंट लगाई जाए तो 205 रुपए पर सिर्फ दो रुपए महीना बनते है। इतनी छोटी रकम को देखकर कई लोग पैसा जमा नही करवाते। सोचते हैं कि चलो अगले महीने जमा करवा देगे।

श्री अध्यक्षः अगर किसी गरीब आदमी को फोर टाइम्ज़ पैनल्टी पड जाए तो उसे हैरासमैंट होती है।

श्री लछमन दास अरोडाः स्पीकर साहब, अगर कोई अमीर आदमी एक साल तक पेमैंट रोक रखेगा तो बोर्ड के पैसे कैसे क्लीयर होगे?

श्री अध्यक्षः सारे आदमी अमीर नही होते, गरीब भी होते है।

सेठ राम दास धमीजाः स्पीकर साहब, जो नोटिस मेरे पास है इसके हिसाब से जो पैनल्टी 9–10 गुणा बनती है जो कि बहुत ज्यादा है?

श्री अध्यक्षः आप इनको बाद में मिल लेना। ये जरुर कुछ न कुछ करेंगे।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फर्ज किया किसी आदमी ने मकान की पहली किस्त जमा करवा दी और उसके बाद वह किसी कारण से मकान नही लेना चाहता तो उसको जो रकम मिलेगी वह पूरी मिलेगी या कुछ पैसा काट कर मिलेगी?

श्री लछमन दास अरोडाः इस बारे में मुझे इस समय मालूम नही है। वैसे भी यह हाउसिंग बोर्ड का मामला है। हमारा ताल्लुक तो पालिसी डिसीजन से होता है। फिर भी मै इस बारे में पता करके इनको अलग से बता दूंगा कि पूरी पैसे वापिस मिलते हैं या कुछ कटते हैं।

श्री भले रामः क्या मंत्री जी बताएंगे कि जब किसी को कोई मकान लेना हो तो उसे पहली किस्त देनी पडती है और उसके बाद में कितनी देनी होती है?

श्री लछमन दास अरोडा: स्पीकर साहब, ऐप्लीके ान के साथ 10 प्रति ात पैसा देना होता है और अलाटमैं के समय 15 प्रति ात देना होता है। बाकी 75 प्रति ात पैसा बराबर दस सलाना किस्तो में देना होता है।

श्री भले राम: क्या मंत्री जी बताएंगे कि हाउसिंग बोर्ड के मकानो का डिस्कि ानरी कोटा अब भी मिनिस्टर या चेयरमैन के पास है, क्योंकि पहले हाउसिंगा बोर्ड के चेयरमैन के पास ऐसा कोटा था और उन्होने बहुत से मकान अपने कोटे में से दिए थे?

श्री अध्यक्ष: आप कोटे में से कोई मकान लेना चाहते है? (हंसी)

Setting up of 132 KVA Sub-Station at Uklana Mandi

***1242. Chaudhri Inder Singh Nain:** Will the Minister for irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Governmentto set up a 132 KV Sub-station at Uklan Mandi of District Hisar; and

(b) if so, the time by which the construction work on the setting up of the aforesaid sub-station is likely to be started and completed togetherwith the estimated cost thereof?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes.

(b) The construction work of 132 KV Sub-station, Uklana at an estimated cost of Rs. 2.8 crores is proposed to be takei in hand in the year 1988-89 and will be completed in about two years time.

चौधरी इन्द्र सिंह नैनः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह सब–स्टे ान कम्पलीट हो जाएगा तो उकलाना मंडी के अलावा और कितने गावं इसके एरिया औफ औप्रे ान में आ जाएंगे?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, नौर्मली इसमें गावों की लिस्ट नही होती कि कौन कौन से गांव एरिया आफ औप्रे ान में आ जांएगे। इस समय उकलाना हांसी 33 के0 वी0 सब–स्टे ान से फीड होती है, जिसकी कैपेसिटी 4x2 एम0 वी0 ए0 और 33/11 के0 वी0 भाामिल है। इसे हिसार–बरवाला–उकलाना लाईन से पावर मिलती है। हालांकि उस एरिया में इस समय कैपेसिटी की कमी नही है लेकिन फिर भी फ्यूचर की जरुरत को देखते हुए हमने उस सब–स्टे ान को अपग्रेड करने का प्रोग्राम बनाया है। यह नरवाना–उकलाना लाइन से फीड होगा। एक करेाड 86 लाख रुपए सब–स्टे ान की कोस्ट आएगी और एक करोड रुपया लाइनो की कंस्ट्रक ान पर लगेगा। इसके लिए जमीन देखी जा रही है। उकलाना मंडी के पास साइट की लोके ान को जल्दी ही फाइनेलाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद जमीन ऐक्वीजी ान की प्रोसीडिंगज़ करेंगे। इसके बाद दो साल में यह सब–स्टे ान पूरा हो जाएगा। इससे उकलाना और उसके इर्द

गिर्द के गावों को लाभ मिलेगा। क्वालिटी आफ पावर भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, उकलाना मंडी में 132 के0 वी0 का सब–स्टे ान बनने के बाद उस एरिया की जो टयूबवैल और डोमैस्टिक कनैक ान की ऐप्लीके ांज पैंडिंग पडी है, क्या वे क्लीयर हो जाएंगी?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः जो ऐप्लीके ांज पैंडिंग पडी है उनको तो उस सब–स्टे ान के बनने से पहले की क्लीयर करने जा रहे है। मार्च, 1985 के जो डिमांड नोटिस थे, उनको कनैक ान दे दिया गया है। उसके आगे के डिमांड नोटिस इ यू कर रहे हैं। पहले हम एक साल में इस हजार टयूबवैल के कनैक ान देते थे, अब यह सरकार आने के बाद मुख्य मंत्री जी ने फैसला किया है कि इनको डबल कर दिया जाए। हम मार्च, 1987 तक 25 हजार कनैक ान रिलीज कर रहे है। इस साल 60 हजार डौमेस्टिक कनेक ान देने का टारगेट था उसको बढाकर डेढ लाख कर दिया है। आने वाले सात महीनो में डेढ लाख डोमैस्टि कनैक ान और 60 हजार टयूबवैल कनैक ान दिए जाएंगे। उकलाना में जो सब–स्टे ान बनेगा यह फ्यूचर की नीडज़ को देखते हुए बना रहे हैं।

श्री नेकी रामः अध्यक्ष महोदय, नया सब–स्टे ान बनने जा रहा है, बडी खु ाी की बात है। लेकिन मैं प्रार्थना करुंगा कि

पहले तो बिजली उकलाना से हिसार जाती है ओर फिर हिसार से वापिस उकलाना को दी जाती है। मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उकलाना को उसके पास से जो लाइन जाती है वहां से बिजली देने की कृपा करेंगे?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, फाइलन लाइन हिसार–बरवाला–उकलाना की है। उकलाना से हिसार बिजली जाने का मतलब ये है कि तार के सिरे दोनो तरफ होते है लेकिन बिजली का फ्लो हिसार की तरफ से होता है। इस बात को आंखो से देखने से पता नही चलता कि फ्लो किस तरफ से आ रहा है। रेलवे लाइन को भी देखने से पता नही चलता कि किधर से आ रही है क्योंकि रेलवे लाइन भी दोनो तरफ से एक जैसी होती है।

चौधरी कुन्दन लालः अध्यक्ष महोदय, मै आपकी मार्फत मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे हलके सफीदों के डडवाल गावं में जो 33 के0 वी0 का सब–स्टे ान लगाया जा रहा है, वह कब तक पूरा हो जाएगा?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः डडवाल गावं के सब–स्टे ान के बारे में तो कोई सवाल पूछा नही गया था, इसलिए मेरे पास इस गावं की कोई सूचना इस समय नही है। सफीदों के अन्दर 33 के0 वी0 का या 66 के0 वी0 का पहले ही

एक सब–स्टे ान है। मुझे यह ठीक तरह से नही पता कि वहां पर 33 के0 वी0 का या 66 के0 वी0 का सब स्टे ान है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मै मंत्री जी से एक जनरल सा सवाल पूछना चाहूंगा। जो लोग बैंको से या इधर उधर से गांव में चक्की वगैरा लगाने के लिए लोन ले लेते हैं, क्या उनको बिजली के कनैक ान देने में प्रोयरिटी है? क्या सरकार इस तरफ वि ोश ध्यान देकर ऐसे कनेक ान प्राथमिकता के आधार पर लोगो के देने का विचार रखती है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: सर हरिजनो के लिए तो प्रोयेरिटी है। फिर भी चक्की के लिए या डोमैस्टिक यूज़ के लिए कनैक ान लेने में ज्यादा समय नही लगता।

Digging of Kehlpa Link Drai in Gohana Sub-Division

***1254. Shri Bhalle Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to dig Kehlpa Link Drain in Gohana Sub-Division; and

(b) if so, the time by which the above said proposal is likely to materialize?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes, Sir. A proposal in this behalf is likely to be put up in the next meeting of the Haryana State Flood Control Board.

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मैने केहल्पा ड्रेन का जिक किया है। इस गावं के पास एक बहुत बडी झील है। इस झील के अन्दर बरसात में तो बहुत अधिक पानी भर जाता है। मैने इस केहल्पा लिंक ड्रेन की खुदाई के लिए कई बार लिखकर भी दिया है और इसकी खुदाई के लिए सरकार की तरफ से भी प्रपोजल बनाई गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस लिंक ड्रेन की खुदाई की प्रपोजल कब बनाई गई थी? मेरा असैम्बली में सवाल आने के बाद इन्होने यह फैसला लिया है कि इस ड्रेन की खुदाई करने के बारे में एक प्रस्ताव हरियाणा राज्य बाढ नियंत्रण बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। मै जानना चाहता हूं कि मेरा सवाल आने से पहले जो हरियाणा राज्य बाढ नियन्त्रण बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें इस ड्रेन की खुदाई का प्रस्ताव क्यो नही रखा गया?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, 1979 मे गोहाना सब–डिवजन के अन्दर केहल्पा ड्रेन बनाने की प्रपोजल इंजीनियर ने दी थी। उस समय इस ड्रेन की खुदाई पर 2.80 लाख रुपए खर्च होने थे। उस समय की प्रपोजल के मुताबिक यह ग्रेविटी फ्लो ड्रेन थी। बाद में जब 1983 में फ्लड आया तो उसके बाद यह ऐक्सपीरियंस हुआ कि ग्रंविटी फ्लो से यह ड्रेन काम नही करेगी। छापडा लिंक ड्रेन में इस का आउट पोल है। अब इसका

रिवाइज्ड ऐस्टिमेट तैयार किया गया है जिसके मुताबिक इस पर तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च होने की संभावना है। 5 लाख रुपया वहां पर खर्च करना चीफ इंजीनियर की कपैसिटी से बाहर था। 11/86 में इसका ऐस्टिमेट सबमिट किया गया है। इसलिए अब इसकी खुदाई का प्रस्ताव फ्लड कंट्रोल बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा। अगर किसी वजह से फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मिटिंग नही होती और इस ड्रेर को बनाये जाने की अरजैंसी हुई तो बगैर बोर्ड की ऐप्रूवल की सी0 एम0 साहब की अनुमति से इसे टेक–अप किया जा सकता है।

श्री नेकी रामः अध्यक्ष महोदय, मेरे हलके के अंदर सरदारे वाला, रोंजांवाली तथा एक या दो गांव और है जिनमें बाढ के दौरान पंजाब का पानी आता है। पंजाब के साथ जो ऐग्रीमैंट हुआ था उसके मुताबिक पंजाब से आए हुए पानी से हरियाणा को जो नुकसान होता है, उसका मुआवजा पंजाब सरकार देगी और हरियाणा से गए हुए पानी से जो पंजाब को नुकसान होगा, उसका मुआवजा हरियाणा सरकार देगी। मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन गावों को पंजाब के पानी से जो नुकसान पहुंचा है, उसका मुआवजा पंजाब से मिल गया है? अगर हां तो वहकितना मिला है? दूसरे क्या वह मुआवजा उन गावों के किसानो को बांट दिया गया है?

श्री अध्यक्ष,: आप बडे समझदार है। आप खुद बताएं कि क्या आपकी सप्लीमैंटरी का इस मेन सवाल से कोई संबंध है?

फिर भी मिनिस्टर साहब चूंकि बडे काबिल है, इसलिए यदि वे बताना चाहते हों तो बता दें।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: जो सवाल इन्होने किया है इसके बारे में मुझे इस समय कोई जानकारी नही है।

Shifting of Liquor Vends

***1229. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to shift to far off places suh liquor vends in the State as are located on the sides of the G.T. Road; and

(b) if so, the time by which such a proposal is likely to materialize

उद्योग मंत्री (श्री श्रीकि ान दास):

(क) वर्तमान नीति (हरियाणा लिकर लाईसैंस नियमावली, 1970) के अनुसार भाराब के ठेके की दूरी राश्ट्रीय मार्ग जी0 टी0 रोड से 100 मीटर से कम नही होगी। परन्तु यह दूरी का प्रतिबन्ध नगरपालिका की सीमा, फरीदाबाद कम्पलैक्स के अन्दर या हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा चलाये गये ठेकों पर लागू नही है। यह नीति अपनाई जा रही हैं।

(ख) प्र न पैदा नही होता।

सेठ राम दास धमीजाः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का मतलब यह है कि बस चालक या ड्राईवर जो है, वे जी0 टी0 रोड के बिल्कुल नजदीक जो भाराब के ठेके पडते है, वहां पर बसों को या ट्रको को रोककर भाराब की बोतल ले आते है और पी लेते है। 100 मीटर का फासला बहुत ज्यादा नही। ड्राईवर गाडी को खडी करके भाग करके बोतल ले आते है। अगर 100 मीटर के फासले को बढा दिया जाए तो उससे कम ऐक्सीडैंटस होंगे। कई जगहो पर तो 100 मीटर से कम दूरी पर ठेके है।जी0टी0 रोड पर और हाईवेज़ पर भाराब के ठेको का फासला 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर होना चाहिए ताकि ड्राइवर आसानी से बोतल ला कर न पी सकें।

श्री अध्यक्षः इनके कहने का मतलब है कि भाराब का ठेका ऐसी जगह पर हो जो ड्राईवरो को सडक पर नजर न आये।

श्री श्रीकि ान दासः 100 मीटर का फासला काफी होता है। अगर जी0 टी0 रोड पर 100 मीटर से कम फासले पर कोई भाराब का ठेका हो तो उसके बारे में बता दें, उसको वहां से दूर कर देंगे।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, जी0 टी0 रोड की बात नही है। हरियाणा की काफी सडके ऐसी है जो गावो से होकर गुजरती है। ऐसी सडको पर भाराब के ठेको का फासला 100 मीटर से कम की दूरी पर ही होता है। मेरे कहने का मतलब यह

है कि ऐसे ठेके बिल्कुल सडक के उपर होते हैं। मिसाल के तौर पर मै बडौदा की बात बताना चाहूंगा। वहां पर भाराब का ठेका हरिजनो की बस्ती के साथ लगता हुआ है। इस ठेके को वहां से हटवाने के लिए कई बार लोग मुझ से मिले है और मैने इस बारे में आगे कहा है लेकिन अभी तक वह ठेका वहां से हटाया नही गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चाहे जी0 टी0 रोड हो या गांव की सडके हो, क्या उन पर भाराब के ठेको का फासला कम से कम 100 मीटर की दूरी पर करेंगे?

श्री श्रीकि ान दासः आम सडको पर तो यह फैसला लागू नही होता। यदि किसी गांव की पंचायत वहां से ठेका हटवाने की प्रस्ताव पास करके देगी तो वहां से उस ठेके को हटा देंगे। यह सरकार का फैसला है।

बहन भाान्ति देवीः अध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ से करनाल की तरफ जब जी0 टी0 रोड पर निकलते है तो रास्ते में कम से कम 7 या 8 भाराब के ठेके नजर आते है जो बिल्कुल जी0 टी0 रोड पर हैं। आपने भी वे देखें होंगे। 100 मीटर का फासला तो सरकार ने तय किया हुआ है लेकिन अगर सडक की चौडाई को ध्यान में रखें तो 100 मीटर का जी0 टी0 रोड पर फासला कोई ज्यादा नही है। इसके अलावा मोहल्लो, गलियों और मंदिरो के आसपास बहुत से भाराब के ठेके हैं। मै अपने हलके करनाल का एक ठेका ढाई साल से हटवाने की कोि ा ा कर रही हूं। वहां के लोग भी उस ठेके को वहां से हटवाने के लिए हिंसा पर उतारु

हो जाते हैं। वहां की 100 महिलाएं मेरे पास आई और कहने लगी कि हम चण्डीगढ चलती है और वहां पर इस ठेके को हटवाने के लिए प्रद ान करेंगी। मैने उनको समझाया कि मै इन बातों के विरुद्ध हूं। मैने उनको यही आ वासन दिलाया है मै इस ठेके को हटवाने की पूरी–पूरी कोि ा ा करुंगी। अब मै इस ठेके को हटवाने के लिए 2 महीने से पूरी पूरी कोि ा ा कर रही हूं। मै यह चाहती हूं कि यह ठेका 28 तारीख आने से पहले पहले वहां से हटा दिया जाए।

श्री अध्यक्षः सेठ साहब, मन्दिरो के आसपास जो ठेके हो, उनको तो वहां से हटवा ही दिया जाये तो ठीक रहेगा।

श्री श्रीकि ान दासः जो सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में मैने कहा है कि भाहरो कीम्यूनिसिपल कमेटीज़ की हद्द में यह 100 मीटर के फासले की बात लागू नही होती। बहन जी इस बारे में मुझ से के मिली थी। मैने हिदायत कर दी है कि जहां से बहिन जी इस ठेके को हटवाना चाहती है, हटा दें।

श्री कंवल सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया है कि जी0 टी0 रोड पर या नै ानल हाई–वे पर जो भाराब के ठेके होते है उनका 100 मीटर का फासला होता है। पंजाब भाड्यूल रोड्ज़ एण्ड कन्ट्रोल आफ अर्बन डिवलैपमैंट ऐक्ट के तहत जी0 टी0 रोड पर 100 मीटर के भीतर कोई बिल्डिंग वगैरा नही बनाई जा सकती। लेकिन जब यह बात म्यूनिसिपल कमेटीज् के

एरिया के लिए आती है तो यह लिमिट खत्म कर देते हैं। मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ये इस बात का विचार करेंगे कि म्यूनिसिपल कमेटीज् की लिमिट्स के अन्दर भी नै ानल हाईवेज़ और जी0 टी0 रोड्ज की तरह हिदायतें लागू की जाएंगी?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मै एक बार चौधरी भले राम जी के घर गोहाना में एक भाादी में गया था। वहां पर जो भाराब का ठेका है, वह इनके घर के बिल्कुल सामने है। इस बारे में मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर वह ठेका पक्का बना रहेगा? (हंसी)

श्री श्रीकि ान दासः जहां तक भाहरो की बात का सम्बन्ध है, यह बात विचाराधीन नही है। जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, अगर एम0 एल0 ए0 साहब चाहते है तो वह वहीं पर रहेगा।

सेठ राम दास धमीजाः स्पीकर साहब, भाहरों में मन्दिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि का तो ध्यान रखना चाहिए। बस अडडों पर भी कही सौ मीटर का फासला पूरा नही होता। जी0 टी0 रोड पर भी 100 मीटर के फासले के अन्दर दुकानें खूली हुई हैं। मिनिस्टर साहब खुद पैमाइ ा करवा लें क्योंकि इनके पास बहुत इन्तजाम है। मै तो पैमाइ ा करवा नही सकता।

श्री श्रीकि ान दासः अगर आनरेबल मैम्बर की नालेज में किसी धार्मिक स्थन के पास कोई भाराब की दुकान हो तो ये मुझे बता दें, उसे हटवा देंगे।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, जैसा चौधरी कंवल सिंह जी ने कहा कि मेरे मकान के पास एक ठेका है यह बात ठीक है। वह रहना तो है ही लेकिन मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ठेके में बैठ कर भाराब पीना लीगल हैं क्योंकि मैने देखा है कि वहां बैठ कर लोग भाराब पीते रहते है?

श्री श्रीकि ान दासः ठेके पर बैठ कर भाराब पीना लीगल नही है।

चौधरी लीला कृश्णः स्पीकर साहब, मै बहिन भाांती देवी और धमीजा साहब का बहुत म कूर हूं क्योंकि इन्होने धार्मिक स्थान के पास भाराब के ठेके न होने की बात की है। इस बारे में मैं भी अर्ज करना चाहता हूं कि

साकी भाराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर,

वरना वह जगह बतादें जहां खुदा न हो।

Setting up of 33 KV Sub-station at Koth Kalan

***1243. Ch. Inder Singh Nain:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a 33 KV sub-station at Koth Kalan of District Hisar; and

(b) if so, the time by which the construction work on the setting up of the aforesaid sub-station is likely to be started and completed togetherwith the estimated cost thereof?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes.

(b) The construction work of the sub-station with an estimated cost of Rs. 25 lacs has already been taken in hand and is likely to be completed by June 1988.

चौधरी इन्द्र सिंह जैनः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जी ने पार्ट (बी) के जवाब में फरमाया है कि–

"The construction work of the sub-station with an estimated cost of Rs. 25 lacs has already been taken in hand....."

लेकिन मै आपके माध्यम से मंत्री जी से रिकवैस्ट करुंगा कि ये मौके पर जल्दी काम भाुरु करवाने का प्रयत्न करें।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, 33 के0 वी0 सब–स्टे ान यहां बनाने का प्रोग्राम है। जमीन ऐक्वायर कर ली है, जमीन का कब्जा भी ले लिया है और डिजाईन वगैरा

सब ऐप्रूव कर दिये हैं। ट्रन्डर्ज भी ऐप्रूव कर दिए है। अब जल्दी ही किसी समय काम भ्रुरु हो सकता है। यह काम जून,1988 से पहले पूरा हो जायेगा। स्पीकर साहब, इस सब–स्टे ान से 10 किलोमीटर लंबी जींद–उचाना लाईन बिछली है जिस पर पांच लाख रुपया खर्च होगा और इस सब–स्टे ान पर 20 लाख रुपया खर्च होगा। कंट्रैक्टर्ज को काम अलौट हो चुका है। मै नैन साहब से दरखास्त करुंगा कि ये भी कंट्रैक्टर्ज को कहें क्योंकि कंट्रैक्टर्ज मोस्टली प्राईवेट आदमी हैं। अगर ये उनको कहेंगे, प्रै ाराइज करेंगे तो वे जल्दी काम भ्रुरु कर देंगे।

Grades for Graduate and under Graduate T.W.Os in the Social Welfare Department

***1255. Shri Bhalle Ram:** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state whether two different grades have been sanctioned for graduate and under graduate Tehsil Welfare Officers working in the Social Welfare Department in the State; if so, the classification thereof?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती करतार देवी): हां। स्नातक तहसील कल्याण अधिकारियों के लिए स्वीकृत रुपये 600–20–700–30–850/900–40–1100 है जबकि दसवीं पास तहसील कल्याण अधिकारियों के लिए स्वीकृत वेतनमान रुपये 525–15–600–20–700/750–30–900 है।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, बहिन जी के पास ऐसा महकमा है जो गरीबो से सम्बन्ध रखता है। हमने किसी महकमें में ऐसा नही देखा कि एक पोस्ट पर काम करने वाले अधिकारियों के दो ग्रेउ हों। लेकिन वैलफेयर डिपार्टमैंट में ग्रेजुएट तहसील वैलफेयर अफसर का स्केल 600—1100 का है और मैट्रिकुलेट तहसील वैलफेयर अफसर का स्केल 525—900 का है। मै मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह डिसक्रिपैन्सी क्यों है और क्या ये इसे दूर करने की कृपा करेंगी?

श्रीमती करतार देवीः स्पीकर साहब, यह बात बहुत पूराने समय से चली आ रही है। पंजाब के अन्दर तहसील वैलफेयर औफिसर्ज का स्केल अलग था और पैप्सू में अलग था। वर्श 1956 में पैप्सू राज्य का पंजाब राज्य में विलय हो गया। तहसील कल्याण अधिकारियों के दो प्रवर्गो का भी विलय किया गया लेकिन उस समय भी इनके अलग अलग वेतनमाल रखे गए। 1962 में तहसील कल्याण अधिकारियों के प्रवर्ग के लिए सेवा नियम बनाये गये। भूतपूर्व पैप्सू के कर्मचारियों के लिए रुपये 80—5—100 का व्यक्तिगत वेतनमान रखा गया। सीधी भर्ती के लिए कम से कम भौक्षणिक योग्यता दसवीं पास निर्धारित की गई और इन अधिकारियों का वेतनमाल रुपये 60—4—80/5—100 रखा गया। इन पदों को केवल अनुसूचित जातियों तथा विमुक्त जातियों से ही भरने का जो उपबन्ध था वह समाप्त कर दिया गया।

स्पीकर साहब, ऐसी बात केवल सो ाल वैलफेयर डिपार्टमैंट में ही नही है कई और विभाागों में भी है लेकिन मै माननीय सदस्य से सहमत हूं कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और इसलिए चौथे सैन्ट्रल पे कमी ान की रिपोर्ट को लागू करने के लिए हमारे यहां जो कमेटी बनी है उसको हमने इनका एक वेतनमान करने के लिए केस भेज दिया है।

श्री भलेरामः स्पीकर साहब, तहसील वैलफेयर औफिसर्ज़ को फील्ड में जाना पडता है क्योंकि इनके पास लोन्ज़ के लिए या दूसरी स्कीम्ज़ के लिए जो फार्मज़ आते है उनकी इन्होने वैरिफिके ान करनी होती है। इनके पास काम तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन व्हीकल का इन्तजाम नही होता। बी0 डी0 पी0 ओ0 और तहसीलदार आदि के पास तो अपनी गाडी होती है लेकिन ये साईकल पर जाते है। हालाकि इनका नाम तहसील वैलफेयर अफसर है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इनके लिए जीप या किसी दूसरी व्हीकल का इन्तजाम किया जाएगा ताकि एफि ाएन्सी बढे और काम जल्दी` निपटे?

श्रीमती करतार देवीः स्पीकर साहब, अभी थोडे ही दिन हुए जब वित्त कल्याण अधिकारियों को जीपें दी गईं। उससे पहले उनके पास भी व्हीकल नही थी। इसलिए अभी तहसील वैलफेयर औफिसर्ज़ को जीप देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही हैं।

चौधरी रो ान लाल आर्यः अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में तहसील वैलफेयर के कितने पद खाली पडे हैं और उनको भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती करतार देवीः स्पीकर साहब, कोई पद खाली नही है। हमारे यहां तहसील वैलफेयर आफिसर्ज़ के 36 पद है जो सारे भरे हुए हैं।

Mr. Speaker: Questions are over.

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

10:00 बजे

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, विधान सभा का सै ान बैठा हुआ है। कल भााम को एक बात सुन कर मुझे बडा दु:ख हुआ। हरियाणा गवर्नमैंट के किसी विभाग की ओर से चण्डीगढ में कल्चरल प्रोग्राम रखा हुआ था, परन्तु हाउस के किसी मैम्बर या मिनिस्टर को कोई इनविटे ान नही दिया गया। यह इस हाउस की गरिमा के खिलाफ बात है कि किसी भी सज्जन को इनविटे ान नही दिया गया। इस बारे में सीरियस नोट लिया जाये और डिपार्टमैंट को भी कहा जाये कि ऐसा क्यों किया गया?

श्री अध्यक्षः ठीक है देख लेंगे।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, पिछले दिनों सरकार ने कुछ गांवो को फोकल विलेजिज़ डिकलेयर किया था। फोकल विपेज का मतलब यह है कि उस गांव में भाहर जैसी ही सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। जिस प्रकार भाहर में सीवरेज सिस्टम, अच्छी सडकें, नर्सरी स्कूल, हस्पताल और बच्चों के लिए सभी सुविधाएं होती है वही उन गावों में होनी चाहिए। मेरे हलके में एक बुटाना गांव को फोकल विलेज डिक्लेयर किया गया था लेकिन वहां इस प्रकार की कोई सुविधा नही है। वहां पर जो नर्सरी स्कूल है उसके साथ ही एक नाला लगता है, जो टूटा पडा है लेकिन उस को अभी तक ठीक नही कराया गया है। दूसरी किस्म की भी सुविधाएं वहां पर नही दी गई हैं। वह नाम का ही फोकल विलेज है। इसलिए मै सरकार से निवेदन करुंगा कि उस गावं में जो नालियां और सडके टूटी पडी है उन्हे ठीक कराया जाये।

श्री अध्यक्षः आप कृप्या बैठिए।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाडियाः स्पीकर साहब, मेरे हलके में भी दो गावं को फोकल विपेज डिक्लेयर किया गया था लेकिन उनकी हालत सामान्य गांव जैसी ही है। आम गावों और उनमें कोई अन्तर नही है। यह केवल एक दिखावा ही है। यहां पर फोकल विपेज का बोर्ड लगा हुआ है लेकिन उन गावों में कोई चेन्ज नही आई है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करुंगी कि जिन गावों को फोकल विपेज का दर्जा दिया गया है उनमें सभी सुविधायें उपलब्ध करायी जाएं।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप कृप्या बैठिए।

सेठ राम दास धमीजाः स्पीकर साहब, मेरे अपने हलके में हाउसिंग बोर्ड की कालोनी है। उस कालोनी में कुल 1100 मकान है। सात सौ एक कमरे वाले है, दो सौ दो कमरे वाले हैं और दो सौ तीन कमरे वाले है। वहां पर न तो नालियां ठीक है, न फ्ल ा सिस्टम ठीक है और न ही सडकें ठीक हैं। सीवरेज सिस्टम भी बिल्कुल नही चलता है। 1100 मकानों में 5500 के करीब आदमी रहते है। इनमें कई मकान तो पांच पांच और दस दस लाख के हैं। जो दो कमरे वाले मकान है उनके सीवरेज का पानी बाहर न जाकर अन्दर ही आ जाता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर इसके निकास तथा अन्य प्रबन्ध करायें जायें ताकि लोगों की दिक्कत दूर हो सके।

श्री अध्यक्षः आपकी बात आ गई है। अब आप कृप्या त ारीफ रखें क्योंकि चौधरी अजमत खां जी भी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अजमत खांः स्पीकर साहब, मेरे मेवात के इलाके में कम से कम आज भी बहुत से इलाके ऐसे है जहां प ाु जोहडों का पानी पीते है। आज उन गावों में मवे ियों के लिए भी पीने का पानी नही है। यह बडी दुखदायी बात है। अब गर्मी का मौसम भाुरु हो गया है। सरौली और गुबराडी जाली–की आदि गावों में जाडे के दिनों में भी पीने का पानी उपलब्ध नही है। उन गावों के

लिए अफसरो ने वायदा किया था कि 31 मार्च, 1986 तक पानी चालू कर दिया जाएगा। वहां पर पानी अभी तक चालू नही हुआ है और भाायद रिकार्ड में उन गावों को कमी ान्ड किया हुआ है लेकिन पीने के लिए सर्दियों मे भी पानी नही है। मै सरकार से दरखास्त करुंगा कि पीने का पानी का तथा जोहडो में मवे ियों के लिए पानी का प्रबन्ध किया जाये। खासतौर पर मेरे नूंह हलके के गांव में पीने का पानी उपलब्ध नही हैं। वहां पर जैसा की बताया गया है कि 491 गावों में से 400 गावों मे पीने का पानी दिया जा चुका है और 1986–87 में 91 गावों को और दे दिया जाएगा। रसूलपूर और जेहटाना गावं में मै और चौधरी भाकरुल्ला जी गए थे। वहां की औरतो ने हमारे सामने सिर से खाली मटके उतार कर फोड दिए क्योंकि पांच साल से वहां पीने का पानी नही हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर जानवरो के लिए और आदमियों के लिए पीने के पानी का जल्दी प्रबन्ध किया जाये। जोहडों मे जिन गावों मे पानी नही है उनमें वि ोश तौर से आकेडा, मेवाती, मालव, भोखपुरा, खेडुला, नूहं, इेहाना, गोहाना, गडूरी और उमरा, उमरी, बदरपूर, राजा का भादस और नूंह डिवीजन के इन से मिलते हुए 50–60 गांव है। हथीन हलके में पचानका, गोहपुर, रुपकाडा, उठावड, मालकून, घुडबली, धीरनका, हुडीर्थल, लखनाका, पहाडपुर इत्यादि 30–40 गावों मे पानी नही है।

श्री अध्यक्षः आप अब बैठे क्योकिं चौधरी लाल जी भी कुछ कहना चाहते है।

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरे हलके में बतौरा, धनौरा, और हुसनी गावों मे से लगी हुई पानी की टूटीयों को उखाडा जा रहा है। पानी तो उनमें आता ही नही है लेकिन उन लगी हुई टूटीयों को भी क्यों उखाडा जा रहा है? मेरे हलके मे पानी की बहुत जरुरत हैं।

श्री अध्यक्षः पानी वाले अफसर तो रिटायर होकर आपके हलके में फिर रहे है। (हंसी)

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, पानी का मामला बडा सीरियस है।

श्री अध्यक्षः ठीक है आप बैठिए, पानी का प्रबन्ध कर दिया जायेगा।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाडियाः स्पीकर साहब, मेरी कांस्टिच्युऐंसी मे, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करती हूं, डिस्ट्रीब्यूटीज़ पर पुल नही है। ये गावं रायपुर, आसलवास, भंडगी, नेहचाना, भूतवास, और साबन आदि है। वहां पर किसानो को तीन तीन और चार चार किलोमीटर घूम कर अपने खेतों मे जाना पडता है। वहां के किसान काफी दिक्कत में हैं। अगर मंत्री महोदय वहां पर पुल बनवाने की व्यवस्थ कर दे ंतो मैं उनकी व्यक्तिगत रुप से आभारी हूंगी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, श्री भले राम जी।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, जैसा कि अभी अजमत खां जी ने पानी के बारे में जिक्र किया कि जोहडो में मवे ियों के लिए पानी नही मिलता है यह बिल्कुल ठीक बात है। मेवात में भी यह समस्या है और हरियाणा के दूसरे भागों मे भी यह समस्या है। जब जोहड भरते हैं तो ऐक्सीयन और एस0 ई0 मंजूरी लेनी पडती है। उन्हे दरखास्त देनी पडती है, जब नहर के पानी के लिए पाइप दबता है। अगर इन पाइपस को परमानैंट तौर पर दबा दिया जाये तो कोई जोहड भरने में दिक्कत नही होगी, बार बार मंजूरी लेने की जरुरत नही पडेगी। मेरे हलके मे जो भावड गांव है वहां के लोगों ने सिक्योरिटी भी जमा कर दी है लेकिन अभी तक वहां कोई प्रबन्ध नही हुआ। इसका हल यही है कि वहां पर परमानैंट तौर पर पाईप दबा दिया जाए जाकि जोहड में पानी खत्म होने पर भरा जा सके।

राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज़ अब गवर्नर एड्रेस पर डिस्क ान होगी। चौधरी हुक्म सिंह जी बोलेंगे।

चौधरी हुक्म सिंह (साल्हावास): स्पीकर साहब, कल हाउस में चौधरी ई वर सिंह जी ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाशण के लिए धन्यवाद का प्रस्ताव रखा, मै उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। राज्यपाल महोद ने अपने भाशण में

सरकार की पिछले साल की कारगुजारी ओर आगे आने वाले साल में जो काम करने हैं, उनके ऊपर प्रका ा डाला है। सबसे पहले गवर्नर साहब ने सतलुज यमुना योजक नहर के निर्माण के बारे में बताया है कि हमारी सरकार भारत सरकार से समय समय पर अनुरोध करती रही है कि एस0 वाई0 एल0 को खुदा भारत सरकार अपने हाथ में ले कर इसका निर्माण कराये। भारत सरकार ने यह फैसला किया था कि एस0 वाई0 एल0 15 अगस्त, 1986 तक बन कर तैयार हो जाएगी लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जितना भारत सरकार पर दबाव डाल सके उतना कम है क्योंकि एस0 वाई0 एल0 का हरियाणा के साथ सीधा लगाव बना हुआ है।

स्पीकर साहब, वर्श 1987–88 में दो हजार पम्पिंग सैट्स लगाने के लिये लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिससे किसानो को काफी फायदा होगा। इसके साथ ही डिवलैपमैंट के मामले में आई0 आर0 डी0 पी0, एन0 आर0 ई0 पी0 तथा आर0 एल0 ई0 पी0 जी0 जैसी स्कीमों का जिक्र किया गया है। इन तीनों स्कीमो से हरियाणा की जनता को बहुत ज्यादा फायदा होना है। मै इस बारे में सरकार से एक अनुरोध करना चाहूंगा। ज्यों–ज्यों यह तीनो स्कीमें गावों में लागू की जाती हैं और इन पर काम किया जाता है त्यों–त्यों इनके लिए कुछ ठेकेदारो की अप्वायमैंट की जाती है। कुछ ठेकेदार हरियाणा से मजदूर न लेकर बाहर के मजदूर ले लेते हैं जो उनको सस्ते मिलते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारे प्रदे ा के मजदूरों को मजदूरी नही मिलती

और उनको इससे वंचित होना पडता है।इसलिए इस बात की तरफ ध्यान दिया जाए कि हमारे प्रदे ा के मजदूरों के लिए यह पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की कोि ा ा की जाये। जिस वक्त तक हमारे प्रदे ा में मजदूर मिलते रहें, उस वक्त तक बाहर के दूसरे प्रदे ाों से मजदूर न लगायें जायें।

बिजली के बारे में भी इस भाशण में जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि आज बिजली किसानों के लिए इतनी जरुरी हो गयी हे कि अगर उसको दिन में 10 काम करने है, तो 8 कामों के लिए उसको बिजली पर निर्भर रहता पडता है। हरेक सेक्टर में आज बिजली की जरुरत बढ गई है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदे ा में बिजली का उत्पादन दूसरे प्रदे ाों के मुकाबले में कम हो रहा हैं। हमारे पानीपत का थर्मल प्लांट और भटिंडा का थर्मल प्लांट एक साथ ही यानि 1975 में बनने भाुरु हुए थे। आज इस बात का रिकार्ड है कि पानीपत का थर्मल प्लांट तो 220 मैगावाट बिजली तैयार करता है और भटिन्डा का थर्मल प्लांट 660 मैगावाट बिजली तैयार करता है। अगर हमारा थर्मल प्लांट भी भटिन्डा को थर्मल प्लांट जितनी ही बिजली पैदा करता तो भाायद आज जो दिक्कत हमारे किसानो को उठानी पड रही है वह न उठानी पडती और जो फैक्टरीयों और किसानो के लिए पावर कट लग रहे हैं वे न लगते। मै सरकार से यह प्रार्थना करुंगा कि इस बात की तफ्ती ा करवाई जाए सिस्टम में कहा पर गडबड रह गई है और क्यों हमारा थर्मल प्लांट इतनी ज्यादा

बिजली पैदा नही कर सका। यह तो जाहिर है कि कही न कहीं हमारे सिस्टम में गडबड जरुर है नही तो हमारा थर्मल प्लांट भी भटिन्डा के मुकाबले मे 660 मैगावाट बिजली तैयार कर सकता था। गवर्नर साहब के अभिभाशण में यह भी बताया गया कि नरवाना, हिसार, भिवानी, पलवल, मूनत और पानीपत तापीय परियोजनाओ के विस्तार के लिए छः अन्य तापीय परियोजनाओ की फिजिबिलिटी रिपोर्टज़ भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। यह बडी अच्छी बात है। इससे प्रदे ा का विकास होगा। किसानो को समय पर पावर मिलेगी, लाईट मिलेगी और किसान ज्यादा पैदावार कर सकेगा। बिजली के मामले में मेरा एक सुझाव और है। अध्यक्ष महोदय, तहसील कोसली में एक तुफान आया था जिसकी वजह से जुलाई–अगस्त में कोसली सब–डिवीजन के 15–20 गावों में बिजली का सारा सिस्टम ही एक तरह से खत्म सा हो गया था। अभी कुछ महीने पहले ही यह सारा सिस्टम ठीक हुआ है। इस बीच में सब–आफिस कोसली ने सभी टयूबवैल्ज़ वाले किसानों को फलैट रेट पर बिजली के बिल भेज दिए हैं। एक तो किसान को समय पर बिजली न मिलने से उसकी बिजाई नही हुई और दूसरे कोई काम भी नही हो सके और ऊपर से उसे बिल भी भेज दिया गया। ऐसा नही होना चाहिए कि जिन 3–4 महीनो के दौरान वहां पर पावर रही ही नही, उसका बिल भेज दिया जाए। मेरी सरकार से गुजारि ा यह है कि जिन फ्लैट् रेट टयूबवैल कनैक् ान वाले किसानो को बिल दिए गये है, वह बिल उनको माफ किए जाने चाहिए। जब इसके लिए महकमें के आफिसर्ज़ से पूछते हैं तो वे

कहते है कि केस ऊपर भेज रखा है। वहां महकमे के आफिसर्ज़ को पता है क्योंकि उन्होने वहां पर इस सिस्टम को ठीक करने के लिए काम किया है इसलिए मै नही समझता कि ऐसे केसिज को भी चीफ इंजीनियर, सैक्रेटरी या सरकार को भेजा जाए। यहां के कन्सर्न्ड एस0 डी0 ओ0, एक्सीयन या एस0 ई0 को ही यह पावर होनी चाहिए कि अगर इस तरह से कोई केस हो जाता है तो वह उसको निपटा सकें। जैसे यदि कहीं पर ट्रांफार्मर डैमेज हो जाता है और उसको अगर 2–3 महीने में बदला जाता है तो इस दौरान के बिलो की माफी के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पडती है। लेकिन मेरा कहना यह है कि पावन उन अधिकारियों को ही होनी चाहिए। अधिकारी बेचारे सच कहते है कि उनको ऊपर से मंजूरी लेनी पडती है। मेरी सरकार से पूरजोर प्रार्थना है कि एस0 डी0 ओ0, ऐक्सीन या एस0 ई0 को ही ऐसे केसिज में माफी देने का अधिकार होना चाहिए। वे ऐसे केसिज में फलैट रेट टयूबवैल कनैक्शन वाले किसानो से ऐप्लीकेशन्ज़ लेकर माफी का फैसला कर दें। इससे किसानो का समय भी नश्ट होने से बचाया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के अभिभाशण में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सरकार ने 113 करोड रुपया, जो खालें पक्की की गयी थी, उनका भी माफ किया है। यह बडी अच्छी और सराहनीय बात है। साथ ही साथ आगे यह भी कहा गया है कि आगे के लिए जितनी पक्की खालें बनानी होगी, वह भी

सरकार बनाती रहेगी। हरियाणा के किसानो को यह एक बहुत बडी सूविधा मिली है। हरियाणा के किसान इस बात के लिए प्रसन्न है और सरकार इस बात के लिए जागरुक है कि किसानों का भला हो सके।

जे0 एल0 एन0 कैनाल और लोहारु उठान स्कीम का भी राज्यपाल महोदय ने जिक्र किया है। उन्होने कहा है कि जे0 एल0 एन0 और लोहारु उठान सिंचाई स्कीम के पूरा हो जाने पर 2.85 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त जमीन की सिचांई हो सकेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमें यह फायदा तब मिल सकता है यदि एस0 वाई0 एल0 कैनाल बन जाये और हमें पानी मिल जाये। यह स्कीम जिस वक्त पहले चौधरी बसी लाल मुख्य मंत्री होते थे, उस वक्त बनाई गयी थी। जे0 एल0 एन0 जुलाई, 1976 में पूरी तरीके से तैयार हो गयी थी। दुर्भाग्य की बात है कि 1977 में जनता पार्टी का राज आया और उन्होने अपने दो–ढाई साल के राज में अपने समय में कभी एक दफा भी दस जे0 वाई0 एल0 कैनाल बनवाने की बात नही की। आज पंजाब में एस0 वाई0 एल0 कैनाल बन रही है। जब यह बनकर तैयार हो जाएगी तो हरियाणा के किसान के खेतों में पानी मिलेगा। यह हरियाणा के लिए बडे ही सौभाग्य की बात है और हरियाणा की जनता की मांग पर चौधरी बंसी लाल दोबारा मुख्य मंत्री बनकर यहां पर आये है। उन्होने आते ही जे0 एल0 एन0 और लोहारु उठान सिंचाई स्कीम को पूरा करने के लिए कदम उठाने भ्रुरु कर दिये हैं ताकि

हरियाणा के किसानों की तरक्की हो सके और हरियाणा के बैकवर्ड इलाके की भुमि में सिंचाई हो सके। इन्होने जनता के सामने यह वायदा भी किया है कि हरियाणा में जितने ऊंचे–2 टीले है या ऊपर इलाके है या रेतीली जमीन है, उन पर भी धान और ईख उगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि धान और ईख पानी के बिना नही उग सकते। इन्होने जनता के बीच में कसम उठाई है कि एस0 वाई0 एल0 को बना कर इन दोनो स्कीमो के द्वारा इस इलाके की उपर जमीन को पानी देकर हरियाणा के किसान को ऊपर उठाएंगे। हरियाणा के किसान का, हरियाणा की जनता का चौधरी बंसी लाल के विवके पर पूरा भरोसा है कि वे एस0 वाई0 एल0 नहर को बनवा कर हरियाणा की जमीन को पानी दिलवाएंगे। वे पूरी उम्मीद करते है कि केवल यही चीफ मिनीस्टर हरियाणा के अन्दर एस0 वाई0 एल0 का पानी ला सकते है।

Mr. Speaker: Please wind up. बहुत से मैम्बर्ज़ ने अभी बोलना हैं।

चौधरी हुक्म सिंहः अध्यक्ष महोदय, ंगवर्नर साहब ने अपने अभिभाशण में हरियाणा के किसान के लिए बहुत सारी सुविधाएं का जिक्र किया है जिससे कि हरियाणा के किसान का हौसला बढे। हरियाणा के किसान ने जो अपने प्रान्त को आगे ले जाने के लिए मेहनत की है उसका भी इसमें जिक्र आया है। उन्होने बताया है कि इस साल 54.90 लाख टन का खाद्यान्न

उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह सब किसान की लगातार मेहनत से ही हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि अभी पिछले दिनो प्रान्त में बहुत सी जगहो पर ओलावृश्टी हुई है जिससे किसानो की फसलो को काफी नुकसान हुआ है ओर कई जगहों पर तो नब्बे प्रति ात नुकसान हुआ है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उन किसानो को उचित मुआवजा दिया जाए। जहां पर किसानो ने टयूबवैल से सिंचाई की हुई है ओर इन लोगो ने खाद भी डाल दिया, बीज भी डाल दिया, और जितना बिजली का बिल था वह भी अदा कर दिया और उसकी फसल बर्बाद हो गई। उनको बचाने के लिए बिजली का बिल माफ कर दिया जाए। यह ठीक है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है और वह कमेटी इस बारे में कार्यवाही कर रही है। मुझे पूरी आ ाा है कि यह कमेटी किसान को अधिक से अधिक मुआवजा दिलवाएंगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः मै मैम्बर साहेबान से रिकवैस्ट करुंगा कि बोलने के लिए ज्यादा समय न लें। दस–दस मिनट में अपना भाशण समाप्त कर दें क्योंकि बोलने वालों की लिस्ट काफी लम्बी है। अब चौधरी साहब सिंह सैनी बोलेंगे।

चौधरी साहब सिंह सैनी (थानेसर): अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के अभिभाशण पर सदन में चर्चा चल रही है। माननीय सदस्य चौधरी ई वर सिंह ने धन्यवाद का जो प्रस्ताव

सदन में रखा है उसके समर्थन मे मैं बोलने के लिए खडा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाशण के पैरा नम्बर 3 में हरियाणा प्रदे ा की तरक्की का जिक्र किया गया है। इसमें कह गया है कि हरियाणा प्रदे ा ने लगातार तरक्की की है और वह आगे बढ रहा है। इसमें ज्यादा योगदान हमारी सरकार का रहा है और पिछले सात आठ महीने से इस तरक्की में और भी ज्यादा गति आई है और हमारा हरियाणा ज्यादा आगे बढा है। अध्यक्ष महोदय, जैसा की आपको पता है, हमारे मुख्य मंत्री जी ने राजीव जी से 403 करोड रुपया हरियाणा के विकास कार्यो के लिए लाकर इस प्रगति में और गति प्रदान की है। हमारे विरोधी पक्ष के भाई इस 403 करोड रुपए आने की आलोचना कर रहे है क्योकि वो हरियाणा की प्रगति को नही देखना चाहते। वे कहते है यह रुपया हरियाणा को नही मिलना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, यह कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो वे कहते है कि हम हरियाणा के हितो की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और जब हरियाणा प्रगति की ओर बढ रहा है, तरक्की कर रहा है और उसके विकास के लिए सैन्टर से पैसा आ रहा है, उसको माली इमदाद केन्द्रीय सरकार से मिल रही है तो वे कहते है कि यह इमदाद नही मिलनी चाहिए। गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाशण में हरियाणा की तरक्की का जो नक ाा खींचा है, यह बहुत ही सराहनीय है। मै समझता हूं कि हमारा प्रदे ा कुछ ही दिनो में सारे भारत के अन्दर नम्बर एक पर आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि जहां हमारा हरियाणासभी क्षेत्रो में आगे बढ रहा है उसके साथ ही साथ

हमारे प्रदे ा में जो इरिगे ान का क्षेत्र है, सिंचाई का मामला है, उसमें अभी कुछ काम होना बाकी है। इस अभिभाशण में एस0 वाई0 एल0 नहर का जिक्र आया है। हमारी सरकार इस मामले में पूर्णतया सजग है और प्रयत्न कर रही है कि वह पानी जल्दी से जल्दी हमें मिले। हमारी सरकार ने भरकस प्रयास किया है कि इस नहर को बनाने का काम जल्दी से जल्दी हो सके लेकिन दूसरी ओर हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों ने एक कमेटी, दो एम0 एल0 एज0 और एक मैम्बर की बनाई। उस कमेटी ने आकर रिपोर्ट दी कि उस नहर पर काम तेजी से चल रहा है। हमारी सरकार की ओर से भी सुरजेवाला जी मौके पर गए और उन्होने कहा कि जितना काम होना चाहिए था उतना काम नही हो रहा है। विरोधी पक्ष की मिटिंग्ज़ में जब लोगो ने पूछा कि आपके एम0 एल0 ए0 तो कहते है कि नहर पर काफी तेजी से काम चल रहा है जबकि ऐसी बात नही है तो विरोधी पक्ष के लीडरो ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। ये लोग हरियाणा की जनता को गुमराह कर रहे है। ये लोग कोई ठोक काम नही कर रहे है। दूसरी तरफ हमारी सरकार इस प्रयत्न में लगी हुई है कि एस0 वाई0 एल0 नहर बनने का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जिससे कि हमें पानी मिल सके। इस बारे में सरकार पूरी तरह से सजग है और पूरा प्रयत्न कर रही है कि यह नहर जल्दी से जल्दी बने।

अध्यक्ष महोदय, सब से बडी खु ाी का बात यह है कि हमारे पडोस में आग लगी है और हमारे यहां बहुत भाांति और

अमन हैं। जब पडोस राज्य में बदअमनी फैली हो, तोड फोड हो रही हो और हमारे प्रदे ा में बिल्कुल अमन चैन हो और कोई जरा भी सर न उठा सके, तो इससे बडी खु ाी की बात और क्या हो सकती है? मै इसके लिए अपनी सरकार को और अपने प्रदे ा की पुलिस को बधाई देता हूं। उन्होने जो भी छुटपुट घटना हुई , उसको पूरी तरह से दबा दिया और उसके बाद किसी की हिम्मत नही हुई कि यहां पर कोई गडबड कर सके। हमरी पुलिस अधिकारियों ने इस दि ाा में बहुत अच्छा काम किया हैं। हमारी सरकार ने पुलिसको काफी फैसीलिटीज दी है जिससे कि वे भविश्य में और भी अच्छा काम कर सके। सरकार ने पुलिस का खाने पीने का भत्ता भी बढाया है और उनका यात्रा भता तथा एच0 ए0 पी0 मधुाबन के कर्मचारियों को अर्बन भत्ता दिया है। इस अभिलाशा के पैरा छः मे इन सब बातो का जिक आता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदे ा जहां सभी क्षेत्रो मे तरक्की कर रहा है वहां इकौनोमिक क्षेत्र में भी आगे बढ रहा है। हमारे प्रदे ा की जो पैरा–कैपिटा इन्कम है वह भी बहुत अच्छी है और यह लगातार बढ रही है। इस बात का जिर्क पैरा सात में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह उन्नति तभी सम्भव हो सकी है जब हमारी सरकान ने अलग–अलग स्कीमें दी है। हरिजन कल्याण निगम को कुछ स्कीमें दी हैं, इकोनौमिकल वीकर सैक ान निगम के लिए अलग स्कीम्ज़ दी है और बीस सूत्री कार्यकम लागू किया है। इन सुविधाओं के अन्तर्गत लोगो को बैंको से कर्जा मिलना

सुलभ हो गया है। बेरोजगार युवक अपना निजी काम भुरु कर सकते है। इकौनोमिक उन्नति सरकार द्वारा इन ठोस पगों के उठाने से ही सम्भव हो सकी है। हमारी सरकान ने एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 जैसी स्कीम्ज़ आरम्भ की जिससे कि गावों के लोगों की काफी उन्नति हुई है ओर गावं के लोगो को रोजगार मिला है। इस सरकार ने गावों के अन्दर स्कूल खोलने, वहां पर कमरे बनाने और हरिजन चौपाल बनाने की दि ाा में भी काफी काम किया है। इन सब स्कीमो के भुरु करने से गांव के गरीब भाइयों, हरिजन भाइयों, जिसके पास जमीन नही है, को काम मिला है और उनकी आर्थिक स्थिती सुधरी है और गावों का विकास हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सब से बडी खु ाी की बात यह है कि हमारा प्रदे ा पैदावार के हिसाब से काफी आगे बढा है। हम अनाज के मामले में अपनी जरुरत को पूरा करने के अलावा दूसरे प्रदे ाो को भी अनाज सप्लाई करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तभी सम्भव हो पाया है जब सरकार ने किसान को अच्छा बीज, अच्छी खाद और समय पर पानी दिया है तथा एग्रीकल्चर विभाग ने वे सारी सुविधाएं किसान को दी है जिनसे उपज बढ सकती है। किसान ने इन सब सुविधाओं का इस्तेमाल किया, उसने मेहनत की और हम आगे बढे। कुरुक्षेत्र जिला सारे प्रदे ा में पैदावार के लिहाज से नम्बर वन पर है लेकिन वहां पर जितनी सहूलियतें किसानो को मिलनी चाहिए थी उतनी अभी भी अवेलेबल नही है। जितना पानी और बिजली मिलनी चाहिए थी उतनी नही मिल रही है। हमारे वहां के किसान बडे मेहनती है। मै

समझता हू कि अगर वहां के किसानो को पानी और बिजली की सहूलियतें मिल जाये ंतो पैदावार आगे से डेढ गुणा ज्यादा हो सकती है। स्पीकर साहब, जैसा कि आपको पता है कि हमारे कुरुक्षेत्र जिला में थानेसर के एरिया में नहर का पानी नही है और बिजली के द्वारा टयूबवैल के जरियें सिंचाई का काम होता है लेकिन उतनी बिजली नही मिल रही है जितनी की किसानो को जरुरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने दादूपूर नलवी और लाडवा में दो नहरो की स्कीमें बनाई हैं। इस बारे में मैने कल भी एक सवाल पूछा था कि इन स्कीमो पर जल्दी ही काम आरम्भ करवाया जाए। आ ाा है कि सरकार इन स्कीमो पर जल्दी ही काम भाुरु कर देगी। इन दोनो स्कीमों पर जितनी जल्दी काम आरम्भ होगा, उतना ही ज्यादा फायदा किसानो को होगा और पैदावार भी बढेगी। इससे जो वाटर लैवल नीचे चला गया है वह भी उपर आ जाएगा। मुख्य मंत्री महोदय 8 फरवरी को रादौर में गये थे और उन्होने वहो पर यह अनाऊंस किया था कि इन दोनों स्कीमो पर जल्द ही काम भाुरु हो जाएगा। इसके लिए मै उनका धन्यवादी हूं कि उन्होने ऐसी आ वासन दिया है।

स्पीकर साहब, जहां तक बिजली का सवाल है, इस बारे मं मै यही कहूंगा कि मेरे एरिया में कुछ सब–स्टे ान नये बनने चाहिएं। अगर वहां 220 के0 वी का सब–स्टे ान लग जाए तो स्थिती मे और सुधार होगा। कैथल में 220 के0 वी0 का एक सब–स्टे ान बन रहा है और स्पीकर साहब, आपके हलके

भााहबाद में भी 220 का सब–स्टे ान बनने में कितनी देर लगे, यह मैं कह नही सकता। मै यह कहूंगा कि भााहबाद में भी 220 के0 वी0 का सब–स्टे ान जल्दी बनना चाहिए और यह काम जल्दी ही होना चाहिए ताकि किसानो को उतना ही जल्दी इसका लाभ हो सके। इससे हमारे सारे हलके को काफी बिजली मिलेगी और लोगो को हर तरह की सहूलियतें मुहैया होगी। इसके अतिरिक्त सरकार की तरफ से जो किसानो को कर्जा, खाद बीज वगैरा की दूसरी सहूलियतें दी गयी है, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। लेकिन कूछेक क्षेत्र ऐसे है जहां पर किसानो को सहूलियतें नही दी गयी है, जैसे हमारे क्षेत्र मे सूखा तो नही पडा लेकिन फिर भी पानी बिजली की कमी रही है जिस की वजह से किसानो को सबसिडी नही मिली। मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि सबसिडी और दूसरी सहूलियतें जो कि दूसरे जिलों के किसानो को दी गयी है, मेरे जिले में भी दी जानी चाहिए ताकि मेरे हलके के किसानों को भी कुछ राहत मिले। फिर मै इसके लिए सरकार की सराहना करता हूं कि जिन–जिन चीजों की किसानो का जरुरत थी, वे चीजें सरकार ने मुहैया की है। इसका जिक्र गवर्नर साहब के अभिभाशण में भी किया गया है।

स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मै सरकार की सराहना करना चाहता हूं कि इस ने मेवात डिवैलपमैंट बोर्ड बनाया। यह भी डिवेलपमैंट करने के लिए अच्छा कदम उठाया गया है। इससे मेवात के एरिया की बडी भारी तरक्की होगी। हमारे प्रदे ा का यह

एरिया भी आगे बढेगा। स्पीकर साहब, पानीपत में जो इक्ट्ठ हुआ था, उसमें सरकार ने बैकवर्ड क्लासिज़ के भाइयों को काफी सहूलियतें मूहैया करने का एलान किया हैं। मिसाल के तौर पर उनको गांव में नम्बरदार और पंच आदि बनाने की सुविधाएं दी जाएंगी और पंचायतो की जमीन में 10 परसैंट हिस्सा भी मिलेगा।

इससे आगे मैं, स्पीकर साहब, एजुके ान के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। सरकार ने सातवी पंचवर्शीय योजना के अन्तर्गत गर्ल्ज़ स्कूल ज्यादा खोलने का जो निर्णय किया है, वह बडा ही सराहनीय कदम है क्योंकि गांव के लोग लडकियों को कम ि ाक्षा दे पाते है। इस तरह से लडकियों के स्कूल खोले जाने से गावों के भाइयों को काफी लाभ होगा। जो दो नवोदय स्कूल खोले गए है इससे टेलेंटैड बच्चो का काफी सहूलियतें मिलेंगी। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि कुरुक्षेत्र में भी इस तरह का स्कूल खोला जाना चाहिए। (घण्टी) इसके साथ ही मैं सैन्ट्रल फोर्थ पे कमि ान की जो रिपोर्ट आई है, उस बारे कुछ कहना चाहूंगा। ऐम्पलाइज को 1–1–1986 से सैंट्रल पे कमि ान की रिपोर्ट के अनुसार जो राहत दी जा रही है यह बहुत ही सराहनीय है। सरकार ने हर पग पर यह कोि ा ा की है कि हरके वर्ग को जितनी भी सहूलियतें मिल सके दी जाए। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इन अलफाज के साथ मैं इस अभिभाशण की, जोकि गवर्नर साहब ने 23 मार्च, 1987 को इस हाउस में दिया और जिसके सम्बन्ध में चौधरी ई वर सिंह जी ने धन्यवाद का

प्रस्ताव रखा व चौधरी कंवल सिंह जी ने जिसका समर्थन किया, पूरजोर हिमायत करता हुआ और आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि मुझे बोलने का समय दिया।

ठाकुर बहादुर सिंह (दडवां कलां): स्पीकर साहब, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। स्पीकर साहब, गवर्नर साहब ने 23 मार्च, 1987 को इस विधान सभा में अभिभाशण दिया और उनका धन्यवाद करने के लिए जो प्रस्ताव चौधरी ई वर सिंह जी और चौधरी कंवल सिंह जी ने यहां पे ा किया, मै उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। गवर्नर साहब ने जिस तरह से हरियाणा सरकार की उपलब्धियों और सरकार के आईन्दा प्रोग्रामज को बतलाया वह इस कदर सराहनीय था कि सारे दे ा के लिए हरियाणा प्रान्त के लिए वह एक मिसाल बन गयी। जो आईन्दा के सरकार के प्रोग्राम्ज है, वे भी आ ाओं के प्रतीक हैं और हरियाणा की जनता की ओर से हम सब को इस बात का गर्व है कि हमारे माननीय मुख्य मत्री महोदय जो कुछ कहते है, उसे वे कर के भी दिखाते है और हरियाणा के हित उन्ही के हाथो में सुरक्षित है।

स्पीकर साहब, गवर्नर साहब ने अपने अभिभाशण में ला एण्ड आर्डर का जिक किया। हरियाणा के अन्दर भाांति और स्थिरता हमारे राज्य की प्रगति के लिए बुनियादी आधार है। हमारे पडोसी राज्य पंजाब में लोागे का जीवन किस कदर दूभर हुआ है यह सबको मालूम है लेकिन हरियाणा सरकार ने इस मामले में

पूरी तरह से कंट्रोल करके दिखा दिया है। यहां पर बडा पीसफूल वातावरण है और जनता बडे भाांत वातावरण में कमा कर खा रही है। इसके लिए हमारे हरियाणा प्रान्त के नेता और योग्य अधिकारीगण, दोनो बधाई के पात्र है। उन्होने पडोसी राज्य में इतना भाोर गुल होते हुए भी अपने राज्य में भाांति को इस कदर बरकरार रखा है कि यहां पर कोई भी ऐसी अनहोनी बात नही होनी दी हैं। इसे हम सब जानते है इसका सारा श्रेय हमारे योग्य नेतृत्व को ही जाता है।

इसके बाद स्पीकर साहब, मै एस0 वाई0 एल0 की बात पर आता हूं। हमारी सरकार के योग्य नेताओ ने इराडी कमि ान के सामने जैसे भी हो अपना केस बहुत खुबसुरती के साथ पे ा किया है ताकि हरियाणा के हितो के किसी प्रकार का धक्का न लगे और हमें अपना पूरा पानी का हिस्सा उपलब्ध हो। इससे हरियाणावासियों का काफी उम्मीद है लेकिन मै यह कहना चाहता हूं कि एस0 वाई0 एल0 की कंस्ट्रक ान का काम बीच में ही रुका पडा है। हरियाणा की जनता की यह मांग है कि इस काम को सैन्टर अपने हाथों में भाीघ्र ही लेकर पूरा करवाए ताकि हरियाणा को इससे लाभ हो सके। यह काम 15 अगस्त, 1986 तक पूरा होना चाहिए था लेकिन वह आज भी उसी तरह लटक रहा है। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि सैन्टर से कहकर इस काम को जल्दी ही पूरा करवाया जाए क्योंकि इससे हरियाणा को काफी लाभ होने वाला है यानी हमारी पैदावार में काफी बढोतरी होगी।

अगर पानी नही मिलेगा तो हरियाणा तरक्की के िशखर पर नही पहूंच पाएगा। इसलिए मेरी रिकवैस्ट है कि इस काम को सैन्टर अपने हाथ में ले। इसके साथ साथ बिजली के मामले में भी अभिभाशण में काफी कुछ कहा गया है। इस समय हरियाणा सरकार 10 हजार के करीब टयूबवैल कनैक्शनज़ लोगों को दे चूकी है और इस साल के अंत तक 25000 टयूबवैल कनैक्शनज और देने का टारगेट है। यह किसानो के हित की बात है। यह पैदावार को बढावा देने की बात है। बिजली की प्रोडक्शन और कंजम्पशन मे जो गैप है उसके लिए जो प्रोग्रामज़ सरकार ने बनाये है, वे सराहनीय है। इसके आगे स्पीकर साहब सरकार की और बहुत सी उपलब्धियां बतायी गयी है जोकि सराहनीय है जैसा कि यमुनानगर के अन्दर 1050 मैगावाट की क्षमता वाले एक थर्मल प्लांट की योजना बनायी गयी है। इसके पहले चरण को केन्द्र द्वारा सहमि दे दी गयी है। इस परियोजना का प्राम्भिक निर्माण कार्य भुरु हो चुका है। इसी तरह से सरकार ने पानीपत तापीय परियोजना मे 210 मैगावाट के 6वें यूनिट के लिए परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है। इसके अलावा भारत सरकार के जो प्रोजैक्ट्स है उन से भी बिजली लेकर हरियाणा के किसानो को बिजली दी जाएगी। यह एक बहत अच्छा विचार हमारी सरकार का है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

जहां तक हमारी आबपाशी का ताल्लुक है, बिजली और नहरें दोनों ही साधन हमारे पास है। नहरों के बारे में मै तजवीज

रखना चाहता हूं। हमारे हरियाणा के इलाके में नहरें तथा खाल पक्के किए जा रहे हैं और उनका खर्चा किसानो से नही लिया जा रहा है। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन कई नहरों के ऊपर पुल नही है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जहां गावं–गावं को सडक से जोडा जा रहा है वहां गांव वालो की दूसरी तरफ जाने के लिए नहरो पर पुल भी बनाएं जाएं। हमारी डिसैंटरेलाइजे ान आफ प्लानिंग की बहुत बढिया स्कीम बनी है। पहले बहुत से प्रोग्राम सैंटरेलाइजे ान के तहत रह जाते थे। अब उनको पूरा करने के लिए साढे पांच करोड रुपया रखा गया है। इससे बहुत बडा फायदा होगा। हमारे बीस प्वायंट प्रोग्राम के तहत गांव–गांव में गरीब आदमियों के लिए साधन जुटाए गये है। आई0 आर0 डी0 पी0, एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 स्कीमो के तहत हम हर गांव में देखते है कि कुछ न कुछ हो रहा है। जहां तक हमारे ड्रिंकिंग वाटर का ताल्लुक है, गावों में वाटर वर्क्स लग चुके हैं। खास कर मेरे इलाके में जहां पीने के पानी की बहुत समस्या हुआ करती थी, आज वहां टूटीयां चलने लग गई हैं। इस समय बहुत थोडे से गांव बाकी हैं जिनके लिए सरकार का पक्का इरादा है कि वहां भी पानी पहुंचाया जाए। इसी तरह से हैल्थ का मामला है। हमारे रोहतक मैडिकल कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्यूट बनाया जा रहा है। यह भी एक बहुत बडी उपलब्धी है। इसी तरह से आज हमें हर गांव में सब–सैन्टर की बिल्डिंग खडी नजर आती है। प्राइमरी हैल्थ सैंटर भी और बढाने का प्रावधान किया गया है। यह भी बहुत अच्छी बात है। इससे ग्रामीण लोगों

का जीवन स्तर ऊंचा होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा ज्यादातर खेती पर निर्भर करता है और यहां की ज्यादातर आबादी किसानों की है। हम आज देखते है कि नौकरी पे ाा, तिजारत पे ाा और किसान पे ाा लोगो की आमदनी में बहुत ज्यादा अन्तर होता जा रहा है। इससे किसान को बहुत बडी परे ाानी खडी हुई है। जागृती में हमे ाा नई सोच बढती है और वह सोच आज किसान में बढी है। किसान का बच्चा आज मुनाफे वाला पे ाा करने की सोच रहा है। किसान का जो बच्चा पढा हुआ है वह नौकरी की तला ा में फिर रहा है। हमारे वजीर और एम0 एल0 ए0 साहेबान भी आज इस चीज से परे ाान हैं। उनके पास हजारो बच्चे अपने पिताओं के साथ आते है और कहते है कि हमें नौकरी दिलाओ। यह समस्या क्यों है? इस बारे में हमारी सरकार ने बहुत विचार किया है लेकिन इसका जो समाधान अब तक सोचा गया है वह काफी नही है। यह ठीक है कि आज पैदावार बढी है और अनाज हम दूसरे सूबो को भेजने लग गए है लेकिन हम किसान की कोस्ट आफ प्रोडक ान की तरफ ध्यान नही दे पाए जोकि बहुत ज्यादा बढ गई है। आज किसान का जो सफेद कमीज नजर आता है वह उसने या तो कोओप्रेटिव बैंक से या आढती से कर्जा लेकर बनवाया हुआ है। अगर यही हालत चलती रही तो एक दिन भयंकर तूफान आएगा और किसान वही का वहीं रह जाएगा। सभी बच्चे मुनाफे वाले धंधे की ओर दौडेंगे। जब कोई बच्चा इंडस्टरी नही लगाएगा या कोई और धंधा नही करेगा तो वह नौकरी की तरफ ही दौडेगा। जहां तक नौकरी की बात है हम सब जानते है

कि नौकरी कितने लोगो को दी जा सकती है। यह बहुत बडी समस्या है। हमें आने वाले तूफान से बचने के लिए किसान को इन–पुट्स में रियायत देनी चाहिए। किसान खेती के लिए जो म ाीनरी यूज़ करता है, उसमें रियायत देनी चाहिए। राजीव गांधी जी ने पिछले दिनो कहा था कि खेती में काम आने वाली चीजो की कीमत कम की जाएगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस तरफ पूरा ध्यान दिया जाए कि किसान को भी अपनी पैदावार का मार्जिन उसी तरह से मिले जिस तरह से दूसरे काम करने वालो को मिलता है। ऐसा न हो कि जो आठ घंटे काम करने वाले है, वे तो फूट खाएं और किसान भूखा मरे। इन भाब्दो के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं क्योंकि इस एड्रेस ने हमारी सरकार की उपलब्धियों और प्रोग्रामो को द ार्शाया है और इससे हमारा भविश्य उज्जवल होगा। धन्यवाद।

सेठ रामदास धमीजा (अम्बाला छावनी): आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा के गवर्नर श्री सय्यद मुजफ्फर हुसैन बर्नी ने जो 23 फरवरी को अपना ऐड्रेस पढा मै उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। चौधरी ई वर सिंह तथा चौधरी कंवल सिंह जी ने जो धन्यवाद को रेजोल्यू ान पे ा किया है, मै उसका समर्थन करता हूं। एड्रेस मे जो सबसे खु ाी की बात आई है वह है कि हरियाणा में अमन, सुख और भाांति रखेंगे। यह बहुत बडी बात है कि पडोसी प्रदे ा में गडबड हो और यहां बिल्कुल भाांती का माहौल हो। इससे अच्छी बात और नही हो सकती। मुख्य मंत्री

जी हर जलसे में यह कहते है कि अल्प संख्यक वर्ग के लोगों की हिफाजत की जाएगी। इस वर्ग के लोगो को यह वि वास भी हो गया है कि सही मायनो में मुख्य मंत्री जी जो कहते है वह करते भी हैं। इसलिए हमारी हिफाजत होगी। ला एण्ड आर्डर की हालत बाकी सूबो की निसबत हरियाणा में बहुत अच्छी है। लेकिन एक बद–किस्मती की बात है। 15 अगस्त 1986 को हमे एस0 वाई0 एल0 का जो पानी मिलना था, वह अभी तक नही मिला। एस0 वाई0 एल0 का पानी हरियाणा की जिन्दगी है और चढते हुए सूरज की किरण है। हम हरियाणा के वासी इस पानी की तरफ अपनी निगाह लगाए बैठे है। जब तक भारत सरकार इस नहर के काम को अपने हाथ में नही लेगी तब तक यह नहर बनने वाली नही है। इसके पानी के बगैर हमारे हरियाणा की धरती प्यासी पडी है। उसकी प्यास बुझाने के लिए इस बारे में जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जाना चाहिए। जब एस0 वाई0 एल0 का हमें पानी मिलेगा उसके बाद हरियाणा की नई राजधानी भारत सरकार बना देगी। उस पर सारा खर्चा भारत सरकार ही करेगी। यह भी बहुत बडी उपलब्धि की बात है। मै अपोजि ान के बारे में भी थोडी सी बात कहना चाहता हूं अपोजि ान यहां से गैर हाजिर है। यह कोई अच्छी प्रथा नही है। लोगों ने इनको इसलिए चुन कर भेजा था कि वे अपने विचार यहां रखते। सरकार अगर कोई गलत काम करती है तो उसकी बात करते या अपने हलके की बात करते। लेकिन जब दो पहलवानो की लडाई होती है और उसमें से एक अपने को कमजोर समझता है तो वह अपने आप मैदान छोड कर

भाग जाता है। इसी तरह से लठ दल वाले भी मैदान छोड कर भाग गए। सही मायनो में जहां तक लोगों का ताल्लुक है उन्होने उनको चुनकर भेजा और अपने फर्ज को पूरा किया लेकिन इन लोगों ने अपने फर्ज को पूरा नही किया। लोंगो ने तो इनको पांच साल के लिए चुन कर भेजा था। ये अम्बाला से दिल्ली की टिकट लेकर बैठे थे और पानीपत से ही वापिस आ गए। सिवाए आपस की लडाई के और ला एण्ड आर्डर को खराब करने के ये कुछ भी नही कर सके। कुरुक्षेत्र में एक जलसे में सी0 एम0 साहब ने व्यापारियों की मांगो पर कुछ अनाउंस किया था। मै व्यापारियों की तरफ से मुख्य मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि जो कुछ भी हमने मांगा था उन्होने उसके मुताबिक रियायत दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सो ाल वैल्फेयर के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। सो ाल वैल्फेयर विभाग ने विधवाओं के लिए और वृद्ध अवस्था वालों के लिए पैन ान का प्रावधान किया है और जो गरीबी की लाईन से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बडे अच्छे काम किए हैं। इस बारे में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अम्बाला कैंट के अन्दर भी गरीब लोगों के लिए 100—100 गज के और 50—50 गज के प्लाट काटे जाए ताकि वे भी सारी सुविधाओं से वहां पर रह सकें। ऐसे प्लाट्स सरकार सस्ते दामो पर दे रही है, जो एक बहुत बढिया काम है।

सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को रा ान में और सफर करने में जो भी रियायतें दी हैं, उसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदे ा कृशि प्रधान दे ा है। यहां पर किसानो के लिए सिंचाई ओर बिजली पर सरकार द्वारा काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। इससे किसानो को काफी राहज मिलेगी।

बैंक वाले लोगो को लोन देने के लिए 5–5 और 10–10 हजार ऐप्लीके ान्ज ले लेते हैं जबकि लोन सिर्फ दो या अढाई सौ आदमियों को ही मिल पाता है। जिन लोगों को लोन नही मिलता है वे निरा ा हो जाते हैं। इस बारे में मेरी सरकार से गुजारि ा है कि लोन की ऐप्लीके ान्ज़ उन्ही लोगों से ली जाएं, जिन्हे लोन दिया जाता हो।

आज प्रदे ा में बिजली की काफी कमी है। सरकार इस कमी को दूर करने की पूरी–पूरी कोि ा ा कर रही है और इसके लिए नई–नई योजनाए बनाई जा रही है। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए अम्बाला छावनी के लिए भी अलग से कोई योजना बनाई जाये ताकि वहां के लोगो की बिजली के संकट का सामना न करना पडे। अम्बाला सिंटी ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमैंट तथा सिटी आफ मिक्सीज के नाम से जाना जाता है। बिजली पूरी न मिलने की वजह से अम्बाला की स्माल स्केल इंडस्टरीज़ का

काफी नुकसान हो रहा है। इस बारे में मेरी सरकार से पुनः गुजारि ा है कि अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी की बिजली की कमी को पूरा करने के लिए अलग से कोई योजना बनाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा से जितने रुपए का माल ऐक्सपोर्ट होता है उसका 1/3 हिस्सा तो अम्बाला से ही ऐक्सपोर्ट होता है। अम्बाला जिला ही सबसे अधिक विदे ाी मुद्रा कमा कर हरियाणा को देता है। अम्बाला छावनी की रोजाना बिजली की खपत 2 लाख युनिट की है। इस में इंडस्ट्रीज़ भी आ जाती है। जगाधरी, नारायणगढ, और दूसरी जगहो पर तो बिजली की सप्लाई ठीक मात्रा में हो जाती है लेकिन अम्बाला के लिए नही हो रही। इसलिए इस तरफ ध्यान दें कर अम्बाला को पूरी बिजली सप्लाई की जाये। जो अम्बाला कैंट का कोटा बनता है, वह तो अम्बाला कैंट को मिलना ही चाहिए।

हमारी सरकार ने किसानो के पक्के खालो का 113 करोड रुपये का कर्ज माफ किया है। इस के लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। जिस दिन एस0 वाई0 एल0 नहर का पानी हरियाणा को मिलेगा उस दिन हरियाणा के जिस आदमी की जेब में 5 रुपये होंगे वे 10 रुपए हो जाएंगे। आज प्रदे ा को सबसे बडी जरुरत एस0 वाई0 एल0 की है। पलवल में हमारे प्राईम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस पर जितना खर्च आएगा, वह सारा पैसा केन्द्र सरकार देगी। यह भी बडी अच्छी बात हरियाणा के लिए है। इसके अलावा जो भारत सरकार ने 403 करोड रुपये दिए

है, उससे हरियाणा की काफी प्रगति होगी। जो पैसा प्रधान मंत्री जी ने हरियाणा को दिया है, उससे पता चलता है कि वे हरियाणा से कितना प्यार करते हैं।

जिस समय हरियाणा बना उस समय यहां पर सिर्फ 4 हजार के आसपास उद्योग धन्धे थे। आज हमारे प्रदे ा में 70461 के आसपास उद्योग धन्धे है। इस काम में हरियाणा ने बहुत अधिक तरक्की की है। दिल्ली में एक नुमाइ ा लगी थी। पी0 ए0 सी0 के साथ हम उस नुमाइ ा को देख कर आए थे। उस नुमाइ ा में हरियाणा का जो स्टाल था, वह बहुत सराहनीय था। आज के दिन कारखाने के मामले में हरियाणा पहली लाईन में खडा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ि ाक्षा के बारे में जिक करुंगा। सातवीं पंचवर्शीय योजना में सरकार लडकियों के लिए 500 स्कूल खोलने जा रही है। अम्बाला छावनी में लडकियों का कोई सरकारी स्कूल नही है। कायदे के हिसाब से जो हमारा हम बनता हो, वह हमें नए स्कूल खोलने का ओर स्कूलो को अपग्रेड करने का मिलना चाहिए। यदि एक लडकी पढती है तो सारा खानदान पढता है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अम्बाला छावनी में लडकियों के ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाएं। टैक्नीकल तालीम की तरफ भी सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे बच्चो को रोजगार मिलेगा।

अब स्वास्थय की बात कहना चाहूंगा। सरकार ने स्वास्थय के लिए काफी अच्छा प्रोग्राम बनाया है। अम्बाला छावनी की आबादी 1 लाख 34 हजार के आसपास है जबकि वहां पर सिर्फ 75 बैड का अस्पताल ही है। इस बारे में मेरी सरकार से गुजारि ा है कि उस 75 बैड के हस्पताल को कम से कम 100 बैड का अव य बनाया जाये। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो आसपास के जो मुलाना और नग्गल वगैरा के हलके लगते है, वहां के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। अम्बाला कैट के पास जो जी0 टी0 रोड है वह ऐक्सीडेंट रोड है। उस रोड पर बहुत ज्यादा र ा रहता है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारि ा है कि अम्बाला छावनी के हस्पताल को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं।

प्लान के मुताबिक सरकार 400 किलोमीटर नई सडके बनाएगी। उस हिसाब से देखा जाए तो अम्बाला का हिस्सा 5 किलोमीटर बैठता है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारि ा है कि पी0 डबल्यू0 डी0 रैस्ट हाउस से टांगरी तक साढे तीन किलोमीटर का फोर लेन का एक टुकडा तैयार किया जाये और डेढ किलोमीटर का टुकडा बबयाल रोड का बनाया जाये।

सरकार ने बाढ नियंत्रण के लिए 12 करोड रुपए रखे है। यदि अम्बाला छावनी को सिर्फ 12 लाख रुपए ही मिल जाएं तो अम्बाला बाढ से बच सकती है। वहां पर सौ साल पुराना गुडगुडिया नाम का एक नाला है। अगर उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया जाये तो भाहर को बाढ से बचाया जा सकता है।

सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिको और उनकी विधवाओं केा सम्मानित किया है। उनको सम्मानित करके सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है। सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है।

हमारी सरकार भारत सरकार की पद्धति के मुताबिक पे कमि ान की रिपोर्ट लागू करके अपने कर्मचारियों को जो सुविधाएं दे रही है, यह भी एक सराहने योग्य काम है।

उपाध्यक्ष महोदय, भाहरियों की आबादी 30 प्रति ात है और देहातियों की आबादी 70 प्रति ात है। 70 प्रति ात टैक्स तो भाहरी देते है और 30 प्रति ात टैक्स देहाती देते है। इसके विपरित सरकार 70 प्रति ात पैसा देहातियों पर खर्च कर रही है। इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि भाहरों को अधिक से अधिक पैसा दिया जाये ताकि उन की सुन्दरता बनी रह सके। आज के दिन भाहरों की हालत बहुत खराब है। म्यूनिसिपल कमेटीज़ के पास इतना पैसा नही है कि वे भाहरो की सफाई का ध्यान अच्छी प्रकार से कर सकें। इसलिए उनको अधिक से अधिक ग्रान्ट दी जानी चाहिए। आज देहात में रहने वाले लोग और भाहर में रहने वाले लोग बराबर की तरक्की कर रहे है।

हमारी कांग्रस पार्टी का 101 साल पुराना इतिहास है। दे ा में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने दे ा के लिए बलिदान किया है और त्याग किया है। कांग्रेस का इतिहास

बलिदान का इतिहास है। दूसरी पार्टियां आज आई कल को बदल गई। इस असैम्बली के 10 सै ान हुए हैं। अपोजी ान के भाईयों मे से एक महानुभाव तो ऐसे है जिन्होने हर सै ान में पार्टी बदली है। उपाध्यक्ष महोदय, इन भाब्दों के साथ मै आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी कुन्दन लाल (सफीदों): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने 23 तारीख को जो अभिभाशण इस विधान सभा में दिया था, मै उसके समर्थन में बोलने के लिए खडा हुआ हूं। जो बातें अभिभाशण में कही गई हैं उससे हरियाणा को चार, चांद लग गए है। इस अभिभाशण में गरीब लोगों के लिए, हरिजन भाइयों के लिए, बैकवर्ड क्लासिज़ के लोगों के लिए और टपरीवासियों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं देने की बात कही गई है। आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, अपोजी ान पार्टी को भी राज करने का सवा दो साल के करीब मौका मिला था। उस समय वे गरीब लोगों के लिए कुछ नही कर सके। अब वे इलैक ान जीतने के लिए गलत आ वासन देकर लोगों को भडका रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने जिन गरीब आदमियों को प्लाट दिए थे, उस समय की सरकार ने वे प्लाट्स छिनने की कोि ा ा की थी। अब जब दोबारा कांग्रेस की सरकार आई तो उसने फिर गरीब तबके के लोगों के लिए अच्छा काम भुरु किया है। अब खास कर करे चौधरी बंसी लाल जी के मुख्य मंत्री बनने के बाद तो गरीब

आदमियों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाया जा रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने व्यापारियों को भी बडी भारी छूट दी है।

11:00 बजे

डिप्टी स्पीकर साहब, इस सरका द्वारा बैकवर्ड क्लासिज के लिए बडी भारी रियायतें दी गई हैं और उन्हे बडी भारी इज्जत भी दी गई है। हमारे गांव में बैकवर्ड क्लासिज़ मे से कोई नम्बरदार नही होता था लेकिन अब नम्बरदारी में भी बैकवर्ड क्लासिज को हिस्सा दिया गया है। इसी तरह से जो नजूल की जमीन थी उसमें भी हमारी बैकवर्ड क्लासिज़ को हिस्सा दिया गया हैं। फिर आप देखें कि पंचायत समितियों में कोई भी बैकवर्ड क्लासिज का भाई नही आता था लेकिन अब उनमें भी हमारे नुमाइंदे लिए जाएंगे। इसी तरह से आप निगमो को देखें। हमारी सरकार ने गरीबों, बैकवर्ड क्लासिज और हरिजनो के उत्थान के लिए अलग–अलग निगम बनाए है। हिन्दुस्तान के किसी भी दूसरे प्रान्त के अन्दर आपको इस तरह के तीन निगम नही मिलेंगे। सारे हिन्दुस्तान में हरियाणा प्रान्त ही एक ऐसा प्रान्त है जहां तीनों निगम मौजूद है। इन निगमो से गरीब, पिछडे वर्ग के लोग और हरिजन भाई अपनी दस्तकारी के काम के लिए, प ा पालन के लिए और किसी भी तरह का काम करने के लिए कर्जा आसान किस्तो तथा सस्ते ब्याज पर ले सकते हैं।

इसके अलावा, हमारी सरकार ने जो मालिया माफ किया है, यह एक बडा अच्छा कदम उठाया है। फिर आपको पता है कि कच्चे खालों को पक्के खाल बनाने पर सरकार का काफी पैसा खर्च आया था और वह किसानो से लिया जाना था लेकिन वह खर्चा भी सरकार ने माफ कर दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, पानी का खूब मात्रा में होना हरियाणा के लिए बहुत जरुरी है क्योंकि यदि किसान खु ाहाल है तो हर आदमी खु ाहाल है चाहे वह बैकवर्ड क्लासिज का आदमी है, चाहे हरिजन है, या दुकानदार है। किसान के खु ाहाल होने से सबको रोजगार मिलता है। किसान प्रदे ा की रीढ की हड्डी है। इसलिए जिस दिन हरियाणा को एस0 वाई0 एल0 का पानी मिल जाएगा उस दिन धमीजा साहब ने तो कहा कि उसका 5 का नोट 10 का हो जाएगा लेकिन मै यह कहता हूं कि उसका नोट 5 की बजाय 20 का होगा और हम इतने खु ाहाल होंगे जिसका मुकाबला नही है। इसके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी भारत सरकार और प्रधान मंत्री जी पर बडा जोर दे रहे हैं कि वे एस0 वाई0 एल0 नहर का काम अपने हाथ में लें। इसी तरह से हमारी जो राजधानी बननी है उसके लिए भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमारे मुख्य मंत्री जी को पूरा आ वासन दिलाया है। इसलिए मै समझता हूं कि सभी कामों के लिए जो स्कीमें बनाई गई है वे सोच समझ कर और सही ढंग से बनाई गई है। यह बडी खु ी की बात है कि हमारी सरकार ने नौजवानो के लिए टैक्नीकल ट्रेनिंग देने तथा दस्तकारी का काम करने के लिए भी

स्कीमें बनाई हैं ताकि हमारे जो पढे लिखे नौजवान है वे बेकार न फिरे।

डिप्टी स्पीकर साहब, मै ज्यादा न कह कर फलड के बारे में जरुर एक बात कहना चाहूंगा। वैसे तो हरियाणा के काफी इलाके में फ्लड आता है लेकिन सफीदो में जबरदस्त फ्लड आता था और चारो तरफ पानी फैल जाता था। आज वहां फ्लड आना रोक कर, पानी को दूसरी जगह भिजवा कर सरकार ने उस इलाके को खु ाहाल बनाया है। आज मेरे जिले में सबसे ज्यादा आमदनी किसान को है। आज वहां जीरी, गन्दम, दूसरी जिन्स और दालें वगैरा सब पैदा होती है। इन भाब्दों के साथ डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपका धन्यवाद करता हूं और अपना स्थान लेता हूं।

चौधरी अजमत खां (नूंह): डिप्टी स्पीकर साहब, गवर्नर साहब के ऐड्रेस पर बहस चल रही हैं। यह बहस चौधरी ई वर सिंह जी ने भाुरु की, चौधरी कंवल सिंह जी ने उसे सैकिंड किया तथा और भी कई सदस्यों ने इसमें भाग लिया। डिपटी स्पीकर साहब, मै तीसरी बार इस बजट अधिवे ान में भााामिल हुआ हूं। हर बार बजट से पहले गवर्नर ऐड्रेस पे ा होता है और कुछ आइन्दा करने का इरादा होता है उनकी तरफ इसमें इ ाारा होता है। इसके अलावा इसमें हमे ाा एक बात कही जाती है कि ''मुझे वि वास है कि आप इस सत्र को अत्यन्त सौजन्य तथा परस्पर तालमेल एवं हरियाणा के लोगेां के उत्तम हितो को ध्यान में रखते हुए सम्पन्न करेंगे।'' कहने का मतलब यह है कि इसमें आपसी

सलाह म ावरे की प्रेरणा दी होती है। लेकिन मै देख रहा हूं कि सलाह म ावरे की बजाय और गैर जरुरी बातें करने में ज्यादा टाईम लेने की कोि ा ा यहां की जाती है। डिप्टी स्पीकर साहब, जो बातें इसमें है मै उनसे बाहर जाकर कुछ नही कहूंगा। इसमें कुछ बातें सरकार की उपलब्धियों की है। वाक्या में हरियाणा इस दे ा का वह सूबा है जो पहले नम्बर पर आने जा रहा है। 1947 में दे ा आजाद हुआ और अपनी सरकार यहां बनी। डैमोक्रेसी में किस तरह की सरकार बने और उसका हैड कैसा हो, यह आवाम पर निर्भर करता है। अच्छा भाासक वही माना जाता है जो आवाम की मर्जी के मुताबिक चलता है और उन्हे खु ाहाल बनाने की कोि ा ा करता है। इसके लिए वे लोग जिन्होने हरियाणा की तरक्की में हिस्सा लिया और कार्य किया मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। सरकार चलाने और डिवलैपमैंट के काम करने के लिए अपने प्रदे ा के लोगों से फंड इकट्ठा करना और उसे सही मायने में यूटिलाइज़ करना यह अक्सर सरकार की नीती होती है। पैसा आवाम का होता है और आवाम पर ही खर्च किया जाता है। परन्तु अच्छा भाासक इस फंड को ठीक ढंग से इकट्ठा करता है सही तरीके से इस्तेमाल करता है और लोगों को सही ढंग से राहत देता है। लेकिन अपने प्रदे ा से फंड इकट्ठा करके खर्च करना अलग बात है और बाहर से पैसा लेकर प्रदे ा में खर्च करना किसी भी भाासक के लिए बहुत ही अच्छी और ऊंची बात है। इसके लिए मैं चौधरी बंसी लाल जी को मुबारकबाद देता हूं। श्री राजव गांधी जी का हरियाणा प्रदे ा पर बहुत बडा अहसान है

और हरियाणा उनका बहुत आभारी है क्योंकि उन्होने हमें 403 करोड रुपए दिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक ला एण्ड आर्डर की बात है, उसके लिए जहां इस सरकार और इसके अफसरों को मुबारकबाद दी जाती है उससे कहीं ज्यादा मुबारिकबाद की मुस्तहक इस प्रदे ा में रहने वाली जनता है जो हर हालत में भाांति और प्रेम का पालन करती रही है। क्यांकि उसकी बदौलत इस प्रदे ा में अमन रहा है। लोग जब अमन बिगाडते है तो प्रदे ा को सम्भालना मु कल हो जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, किसी भी प्रदे ा या दे ा का अमन बनाने और बिगाडने में पोलिटि ायन्ज़ और पुलिस का अहम रोल रहता है जैसा कि पंजाब के हालात से साबित है। लेकिन हमारे प्रदे ा में दोनों ही बातें ठीक हैं। यहां ऐडमिनिस्ट्रे ान और पालिटि ायन्ज़ दोनो ने प्रदे ा को फिरकापरस्ती से बचाने के लिए काम किया है। अलबता, मै एक बात और जरुर कहूंगा कि इतना होने के बावजूद भी कई बार यहां भी प्र ाासको की ओर से ज्यादती हो जाती है। 1947 के बाद मेवात में कई बार पुलिस की गोलियों से लोग मारे गए हैं लेकिन अब 12–22 दिसम्बर की रात को पहली बार छोटल्ली सरपंच को ट्रक में बैठे हुए सामने से ट्रक रोक कर गाली मारी गई। अफसोस इस बात का है कि उस आदमी ने चूंकि भ्रश्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी इसलिए उसकी जबान हमे ाा के लिए बन्द कर दी गई। इसके अलावा एक जूल्म जो

1947 के बाद पहली बार हुआ वह यह है कि मस्जिद में घुसकर पुलिस ने नमाज पढते लोगो पर लाठियां बरसाई जिससे बहुत से लोगों के हाथ पैर टूट गए। पवित्र स्थान का अपमान हुआ और यह सब पुलिस ने जान बुझ कर लोगो को भडकाने के लिए किया। ऐसे पुलिस अफसरो के साथ सख्ती से निपटना चाहिए था, जिन्होने बहुत से लोगों के हाथ पैर तोड डाले, मस्जिद का अपमान किया परन्तु जिम्मेदार अफसरो का तबादला तक नही किया गया। उल्टे लोगेां पर झूठे केस बनाए गए है। मेवात मे इससे बेहद बेचैनी है और हम जनता के सामने जवाब नही दे सकते।

डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली के बारे में भी गवर्नर ऐड्रेस में जिक आया है लेकिन कई जगह सरकार के देखते की बात है। धारुहेडा में पिछले 6 महीने से कुछ इंडस्टरीज़ को राउन्ड दि क्लोक बिजली मिल रही है जबकि किसान को दो घंटे के लिए बिजली नही मिलती। सरकार का यह फर्ज बनता है कि वह इस तरफ तवज्जोह दे। जिन लोगो को पैदावार बढाने के लिए बिजली मिलना जरुरी है उन्हे भी बिजली न मिल तो यह कोई अच्छी बात नही और फैक्टरी वालो को राउन्ड दी क्लोक बिजली मिले इससे तो यही सिद्ध होता है कि बिजली तो है लेकिन किसान के लिए नही। 12–1–1987 को ईस्ट इंडिया, धारुहेडा मे जब विजिलैंस ने छापा मारा तो फैक्टरी बिजली से चल रही थी जबकि 6–1–1987 से 15–1–1987 तक एक मैगावाट और अधिक बिजली खपत करने वाले उद्योगों की बिजली बंद थी। मै एक बात

और कहना चाहता हूं कि जहां सरकार लोगो के काम करने के लिए बाध्य है और अच्छे काम करने से इलाके में खु ाहाली आती है, वहां दसरा पहलू इंसाफ का भी है। जहां पर इंसाफ है वहां पर सरकार और पार्टियां टिकती हैं। मेवात में तरक्की के काम नही किये गये जितने दूसरी इलाको में हुए, यह इंसाफ नही है। मेवात जब पिछड गया तब मेवात बोर्ड बना, यह बोर्ड पिछडेपन की बजाय खुद मुहं बोलती तस्वीर है। मेवात किसी से भी पीछे नही था लेकिन दे ा आजाद होने के बाद वहां पर इतनी प्रगति नही हुई जितनी होनी चाहिए थी। हरियाणा प्रान्त में पानी आया, दूसरे हिस्सों में पहुंचा, 500–600 फुट उंचे भिवानी के टिल्लो पर पहुंचा लेकिन मेवात की हमवार जमीन पर नही पहूंचा। इसी कारण से मेवात का इलाका पीछे रहा। सरकार को मेवात डिवैलपमैंट बोर्ड बनाना पडा और जिसके लिए सारे भाई हाउस में प्र ांसा करते है लेकिन मेवात बोर्ड बोर्ड बना कर मेवात के लोगों पर कोई अहसान नही किया है। बोर्ड बनाने का कारण क्या है? यही ना कि मेवात और इलाको से पीछे था। अब सवाल यह है कि मेवात पीछे क्यों रहा? यहां पर कोई विदे ाी सरकार नही है। हरियाणा मे रहने वाले लोगों की ही सरकार है लेकिन फिर भी मेवात पीछे रहा और आज भी पीछे है। मेरे पास ऐजुके ान के कुछ आंकडे हैं। हरियाणा में 1632 हाई स्कूल सरकार के हैं जिन मे से लगभग 40 मेवात में है। पिछले साल जो हाई स्कूल खोले है उनकी भी पोजी ान आप देख लें। तो ाम हलके में 1986–87 में 7 हाई स्कूल खोले है और पांच मिडिल स्कूल खोले गए जबकि नूंह और

फिरोजपूर झिरका में एक–एक हाई स्कूल और एक–एक मिडिल स्कूल खोले गए है। इसी प्रकार बिजली और पानी की भी यही पोजी ान है। हम सभी बातो ंमे पीछे है। क्या मेवात हरियाणा का हिस्सा नही है? अगर है तो यह पिछडेपन का गन्का नि ाान उस पर क्यों है? अगर यह नि ाान हरियाणा में रहता है तो हरियाणा एक नम्बर सूबा कहलाने का मुस्तहक नही है। मेवात में हुई किन किन नाइन्साफियों का मै जिक करु? मै और ज्यादा न कहते हुए एक बात अव य कहूंगा कि मेवात में अभी भी जोहडी में मवे ायों के लिए पीने का पानी नही है। वहां पर मवे ायों के लिए पीने का पानी जमुना से आगरा गुडगांवा कैनाल द्वारा आराम से उपलब्ध हो सकता है। जमुना से पानी लाने तथा मेवात के फ्लड के पानी को कन्ट्रोल करने के लिए कोटला पम्प हाउस बना, इस पर 1969 में कार्य भारु हुआ और अब तक सारे काम पर लगभग 18–20 करोड रुपये खर्च हो चुका बताया जाता है। लेकिन अभी तक यह स्कीम अधुरी पडी है। जमुना के पानी को स्टोर किया जा सकता है और उस इलाके में एस0 वाई0 एल0 के पानी के न आने की तब तक जरुरत पूरी हो सकती है। अगर जमुना से गुडगांव कैनाल द्वारा पानी को बरसात के दिनो में इकट्ठा कर दिया जाए तो उसी से मेवात को सैराब किया जा सकता है। एस0 वाई0 एल0 के पानी से हरियाणा के लोगो को खु ाी होगी। परन्तु मेवात कैनाल बनने से ही इस इलाके में पानी एस0 वाई0 एल0 का आएगा और लोगों को खु ाी होगी। जब तक यह कैनाल नही बनेगी वहां पर एस0 वाई0 एल0 द्वारा सिंचाई नही हो

सकती। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करुंगा कि पहले इस मेवात कैनाल को तुरन्त बनवाया जाए ताकि एस0 वाई0 एल0 कैनाल के पानी से हमें भी हिस्सा मिले और खु ी हो। यह नहर जब तक नही बनेगी तब तक हमें एस0 वाई0 एल0 कैनाल के पानी का कोई लाभ नही होगा। इगर इसी तरह से यह काम लटकता रहा तो कम से कम दस साल और नहर के बनने में लग जाएंगे और हम पिछड जायेंगे।

मै एक बात और मेवात के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मेरे पास उसके आंकडे भी हैं। डिसैन्ट्रेलाइजे ान स्कीम चली। तीन लाख 63 हजार रुपये नूंह ब्लाक के लिए मंजूर हुए। नूंह ब्लाक में ताउडू ओर नूंह का एरिया भी पडता है। मेरे हलके में इसमें चौपालो के लिए 6 हजार और स्कूलो के लिए 7 हजार रुपए मिले। हमें कुल 13 हजार रुपए दिये गए और ताउडू के लिए बाकी के साढे तीन लाख रुपये दिये गये, अफसरो ने मुझे पूछा तक नही। 3.63 लाख रुपये मे से मेरे हलके में हरिजन चौपाल और स्कूलो के लिए केवल 13 हजार रुपये आये। मेरे पास सारी रिपोर्ट है। इसलिए मै सरकार से निवेदन करुंगा कि काम करते समय बिना–लिहाज, बिना पार्टी, बिना मजहब, ऊंच–नीच के सब लोगों को इन्साफ मिलना चाहिए। इन अल्फाज के साथ मैं गवर्नर साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आ ाा करता हूं कि उन्नती के कार्यो के साथ साथ लोगों को इन्साफ भी मिलेगा।

चौधरी लीला कृश्ण (फतेहाबाद): डिप्टी स्पीकर साहब, मै आपका बहुत धन्यवादी हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। डिप्टी स्पीकर साहब चौधरी ई वर सिंह की ओर से जो मो ान आफ थैंकस गवर्नर साहब के लिए पे ा हुआ है, मै उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। मै हाउस का ज्यादा समय न लेते हुए थोडे ही समय मे कुछ बातें कहना चाहूंगा। हम सभी गवर्नर साहब के आभारी है कि उन्होने 23 फरवरी,1987 को इस महान सदन मे आ कर हमारी सरकार की उपलब्धियों और पालिसिज़ के बारे में बताया।

इसमें कोई दो राय नही कि हरियाणा ने सभी क्षेत्रो मे चहुमुखी उन्नती की है। हरियाणा में ग्रीन रैवोल्यू ान और इंडस्टरीयल रैवोल्यु ान आया है। आज हरियाणा सारे दे ा में पहले नम्बर का सूबा बनने जा रहा है लेकिन यहां पर अभी भी कई समस्याएं मुह बाये खडी हैं। वह दिन मुझे याद है जब यह अनाउन्समैंट हुई थी कि एस0 वाई0 एल0 का 3.5 एम0 ए0 एफ0 पानी हरियाणा के हिस्से में आयेगा। उस दिन हरियाणा में दीपावली मनायी गई थी लेकिन इस एवार्ड को इम्पलीमैंट करने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। उन्होने कई साल पहले कपूरी गांव में एस0 वाई0 एल0 का उदधाटन किया था। उसके बाद एक और समझौता हुआ कि 15 अगस्त, 1986 तक यह नहर मुकम्मल होगी और हरियाणा के खेतों की प्यास बुझेगी लेकिन उस समय तक भी वह पूरी नही हुई।

उसमें अकाली दल ने रुकावट डाली, जिससे धार्मिक झगडे ओर उग्रवाद पनपा। आज तक यह स्कीम अधुरी पडी हुई है लेकिन फिर भी हम आ ाावादी हैं और वह दिन दूर नही जब एस0 वाई0 एल0 मुकम्मल होगी और हरियाणा के खेतों की प्यास बुझेगी। हम अपने मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी के भी धन्यवादी है कि उन्होने प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को पलवल में बुलाया और यह घोशणा करायी कि एस0 वाई0 एल0 का तमाम खर्चा भारत सरकार देगी और यह भी कहा कि जो खर्चा अब तक हो चुका है वह भी भारत सरकार वापिस देगी। अगर इसमें ये भाब्द और जोड दिये जाते कि एस0 वाई0 एल0 नहर भारत सरकार ही बनायेगी तो लोगों को और भी अधिक प्रसन्नता होती। मैं इस महान सदन में यह मांग करता हूं कि एस0 वाई0 एल0 भारत सरकार बनये वरना ये कोरे वायदे ही होंगे। आपको पता है कि सात साल तक चौधरी भजन लाल चीफ मिनिस्टर रहे। केवल दो साल ही चौधरी देवी लाल चीफ मिनिस्टर रहे थे क्योंकि उनकी सरकार टूट गई थी। सात साल पहले चौधरी बंसी लाल जी चीफ मिनिस्टर रहे थे और अब फिर दुबारा चीफ मिनीस्टर बने है। 16–16 साल तक कांग्रेस के ही मुख्य मंत्री रहे है लेकिन हमारी नहर अभी तक पूरी नही हो पायी है। हरियाणा ने हर क्षेत्र में चहुमुखी उन्नती की है। यह छोटी सी स्टेट 15–16 साल में ि ाखर पर पहुंच गई है। इसका श्रेय चौधरी बंसी लाल जी को ही जाता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, ला एण्ड आर्डर की पोजी ान भी गवर्नर साहब ने बताई है। जब से चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री आये है तब से हरियाणा की रंगत ही बदल गई है। इन्होने नगर नगर और गांव गांव में सद्भावना यात्रा की है। साम्प्रदायिक एकता के लिए बडी भारी मीटिंगे की है। उन मिटींगो में बडी जोरदार हाजिरी हुई है जिसके कारण सामप्रदायिक एकता बढी है। मै यह कहने से गुरेज नही करता कि चौधरी बंसी लाल ने जात–पात के भेद को समाप्त करने का पूरा प्रयत्न किया है। बंसी लाल जी ठीक ही कहते हैं:–

मजहब नही सिखाता आपस में बैर रखना।

हिन्दी है हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा।

उनके आने से साम्प्रदायिक एकता बढी है। हरियाणा में भाांतिप्रिय लोग बसते हैं। इसलिए वह दिन दूर नही जब हरियाणा एक नम्बर का राज्य बनेगा और हरियाणा में खु ाहाली होगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे बडे दुख के साथ कहना पड रहा है कि इस सै ान में भी अपोजी ान के सदस्य नही हैं। लोगों ने इसलिए उनको नुमाइन्दा बना कर भेजा था कि वे यहां आ कर उनकी तकलीफें रखेंगे, उनके लिए अच्छे कानून बनवाएंगे लेकिन उन्होने फर्ज को नही निभाया। यह ईमानदारी नही है। वह दिन दूर नही जब जनता उन्हे मजबूर करेगी और उनसे जवाबतलबी करेगी कि आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया हैं?

जनता उनसे कहेगी कि तुमको इलैक ान लडते का अधिकार नही है क्यांकि तुमने अपने फर्ज को पहले भी नही निभाया हैं। हमारे हरियाणा में हर क्षेत्र में तरक्की हुई है, किसान खु ा है लेकिन कभी कभी फलड या ओले आ जाते है जिसके कारण से नुकासान हो जाता है। आजकल तो कभी कभी उग्रवादी नहर को भी तोड देते है लेकिन फिर भी हमारे किसान आ ाावादी हैं। सरकार ने किसानो के लिए बिजली मुहैया की है और दूसरे डिवैलपमैंटके काम भी किये है। इरीगे ान के लिए भी नहरों का जाल बिछा रहे है। मेरी फतेहाबाद कांस्टीच्यूएंसी के बारे में श्री सुरजेवाला जी से विनती है कि जो 45 किलोमीटर लम्बी नहर सारे रतिया और फतेहाबाद के इलाके को सैराब करती है उसके बारे में आज मुझे प्रार्थना करते करते तीन साल हो गये कि इसके पक्का किया जाये। इसके फाल्ज को दूर करके इसके बैंडेज को ऊंचा किया जाये जिससे लाखों एकड धरती सैराब हो सके। सुरजेवाला जी पिछले महीने ही हिसार आये थे। उन्होने सारी समस्या पूछी थी। मै इनसे एक बार फिर यह प्रार्थना करुंगा कि फतेहाबाद डिस्ट्रीब्यूटर की जल्दी से जल्दी लाइनिंग की जाये ताकि लाखों एकड जमीन सैराब हो सके। डिप्टी स्पीकर साहब, आप देंखें कि सारे हरियाणा में टूरिस्ट काम्पलैक्स बने हुए है, बस स्टेण्ड बने हुए हैं, रोड्ज बनी हुई है तथा और सारे तरक्की के काम हो रहे हैं। इन सारी बातों का श्रेय यहां की सरकार को और यहां के आफिसर्ज़ को जाता है। इन भाब्दों के साथ मै आपका एक बार फिर धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

बहन भाांति देवी (करनाल): उपाध्यक्ष महोदय, मै भी आपके माध्यम से माननीय गवर्नर साहब ने जो अभिभाशण दिया था, उसका समर्थन करती हूं और उनका धन्यवाद करती हूं। सभी जानते है कि जब से हरियाणा का निर्माण हुआ है उससे पहले तक हरियाणा वाला इलाका पिछडा इलाका माना जाता था। हरियाणा का निर्माण होते ही यहां विकास कार्य आरम्भ हुए और हरियाणा आगे बढने लगा। जब चौधरी बंसी लाल जी, पहली बार मुख्य मंत्री बने तो उनके समय में निर्माण कार्य की गति इतनी तीव्र थी कि वे हरियाणा को दूसरे प्रदे ाो के मुकाबले में आगे बढाकर दे ा में उसे दूसरे नम्बर पर ले आये और आजकल जो प्रयत्न चल रहे हैं उनसे अब वह समय आने वाला है, जब हमारे मुख्य मंत्री जी हरियाणा को पहले स्थान पर ले आएंगे। इस निरन्तर विकास का एक कारण यह है कि यहां कानून और व्यवस्था बहुत अच्छी रही है जिसकी वजह से लोग भाांति पूर्वक रह कर अपनी रोजीरोटी कमाने का धन्धा करते हैं चाहे वह खेतीबाडी है, कृशि है, इंडस्टरी है, व्यापार है अथवा नौकरी है। ये काम यहां पर ठीक से हो रहे हैं। इसके साथ ही बीच में कुछ समय ऐसा भी आया जब एस0 वाई0 एल0 नहर बनने वाली थी। उस समय सरकार ने बहुत सा पैसा एस0 वाई0 एल0 के निर्माण पर खर्च किया। निर्माण कार्य बीच में भी रुक गया था लेकिन आज हमारे मुख्य मंत्री चौधरी बसी लाल जी के आने पर वह समस्या भी एक तरह से हल हो गई। पिछले दिनो तक जो पैसा खर्च किया गया था वह भी केन्द्रीय सरकार लौटा रही है। इसके

साथ ही चौधरी साहब ने 403 करोड रुपया प्राप्त किया जिसके द्वारा हरियाणा का नव–निर्माण हो सकेगा और हरियाणा प्रगति कर सकेगा। इस प्रदे ा की पहले से भाक्ति बढी है क्योंकि यहां पर कानून और व्यवस्था ठीक रही है। यहां पर चाहे कोई हिन्दू है, मुसलमान है, सिक्ख है, सभी भाई भाई की तरह से रह रहे है। इनका परस्पर कोई भी भेदभाव नही है। क्योंकि किसी का किसी से कोई संधर्श या दु मनी नही है। यह जो कानून और व्यवस्था हमारे प्रदे ा में ठीक रही है इसके लिए हमारे भाासन का और प्र ाासन का सहयोग रहा है। पुलिस बल ने भी सहयोग दिया हैं। इसलिए पुलिस के मनोबल को बढाने के लिए सरकार की तरफ से उनकी मदद की गई है। सौ रुपए मासिक रा ान भत्ता वेतन कर्मचारी से लेकर अधिकारी वर्ग तक बिना किसी भेदभाव के दिया गया है। इसके अलावा 20 रुपये मासिक जमा कराने पर वर्दी पहने जो भी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी यात्रा करेगा, उनको हरियाणा परिवहन में नि ाुल्क यात्रा की स्वीकृती भी दी गयी है। प्रदे ा सरकार यह भी सोचती है कि यहां के लोगो का स्वास्थय ठीक रहे। मनुश्य को मानसिक तौर पर, भाारीरिक तौर पर और सामाजिक तौर पर ठीक रखने के लिए वातावरण या पर्यावरण का ठीक होना बहुत जरुरी है। इसलिए वनो की तरफ भी बडा प्रयत्न चल रहा है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगायें जायें। इस काम के लिए 64 करोड रुपया रखा गया है ताकि अधिक से अधिक पौधे लगा कर लोगो के स्वास्थय को ठीक रखा जा सके। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और हरिजन जातियों की जो बस्तियां है, उनमें

सुधार के काम किये गये है। बच्चो की पढाई के लिए भी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन आई0 आर0 डी0 पी0 एन0 आर0 ई0 पी0 तथा आर0 एल0 ई0 जे0 पी0 स्कीमो के अन्तर्गत लोगों को बहुत सारे दिवस तक काम देकर उनकी मदद की गयी है। इसके अलावा स्वतः रोजगार कार्यक्रम के अधीन भी लाखो लोगों को काम दिया गया है। खालों को पक्का करने का जो खर्चा माफ किया गया है उससे भी लौगों को काफी राहत मिली है। इसके अतिरिक्त पानी की जो सुविधा दी गई है, वह बहुत अच्छी है। जहां पर सिंचाई की बात तो दूर पीने के लिए मीठा पानी भी नही मिलता था, वहां पर मुख्य मंत्री जी के प्रयत्न से पानी दिया गया है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने तो पक्की नहरो को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाकर सूखी धरती की प्यास ही नही बुझाई है बल्कि नमकीन पानी पीने वालो को मीठा पानी भी पीने को दिया है। इसके अलावा किसानो के सहयोग के लिए प ा हस्पताल भी खोले गये है। ि ाक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रबन्ध है। कई प्राइमरी स्कूलो को मिडिल स्कूल के रुप में अपग्रेड किया गया है। इन भाब्दों के साथ मैं इस अभिभाशण का समर्थन करती हूं और आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे समय दिया।

चौधरी सूबे सिंह पुनिया(उचाला कलां): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने 23 तारीख को जो अभिभाशण इस हाउस में दिया है जिस पर चौधरी ई वर सिंह

जी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, मै उसका समर्थन करने के लिए खडा हुआ हूं। राज्यपाल का अभिभाशण एक ऐसा दस्तावेज है जोकि सरकार की पिछले वर्श की उपलब्धियों नीतियों, कार्यकमो और आगामी वर्श के लिए योजनाओ, कार्यकमो और नीतियों की झलक होता है। सरकार की क्या उपलब्धियां रही है, ये इसमें बताई गयी हैं। सबसे बडी बात जो आज दे ा के सामने जवलन्त समस्या बन कर खडी हुई है और हरेक नागरिक के मन में उठ रही है वह है पंजाब समस्या या उग्रवाद की समस्या। पंजाब हमारा पडोसी राज्य है। उस समस्या से या उस आग से बचा कर प्रदे ा को रखना ओर कानून और व्यवस्था की स्थिती बनाये रखना, इस सरकार की एक मुख्य उपलब्धि रही है। दूसरा, प्रदे ा के हर नागरिक के मन में जो सवाल है वि ोशकर यहां के हर किसान के मन में है, वह है सतलुज यमुना योजक नहर का निर्माण। उपाध्यक्ष महोदय, सतलुज यमुना लिंक नहर जिसको एस0 वाई0 एल0 नहर कहते हैं, पंजाब समझौते के मुताबिक 15 अगस्त, 1986 तक बनकर तैयार हो जानी चाहिए थी लेकिन कतिपय कारणें से इस नहर का कार्य अभी तक पूरा नही हो पाया है। मै आदरणीय मुख्य मंत्री जी की और सरकार की इस बात के लिए प्र ंसा करुंगा कि वे केन्द्र सरकार पर यह दबाव डाल रहे है कि वह इस नहर का निर्माण कार्य अपने हाथों में ले। केन्द्र सरकार को इस नहर के निर्माण कार्य को अपने हाथों में लेने के लिए कहना वाकई प्र ंसनिय कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा का नौजवान किसान इस बात की प्रतीक्षा में है कि हमारी जमीन में

जल्दी से एस0 वाई0 एल0 का पानी लगे। हमारे खेत मे हरियाली आए, घर में खु ाहाली आए और जीवन स्तर ऊंचा हो। उपाध्यक्ष महोदय, मै एक और बात के लिए सरकार की भूरी–भूरी प्र ांसा करुंगा कि पंजाब समझौते के फलस्वरुप हरियाणा अपनी राजधानी, जोकि दुनिया का सर्वोत्तम भाहर होगा, बनाने का संकल्प बार बार केन्द्रीय सरकार पर जाहिर कर रहा है। मै एक वि ोश बात कहना चाहता हूं कि जो हमारी पंचवर्शीय योजनाएं है उनके द्वारा विकास के लिए समृद्धि के लिए, और निर्माण के लिए जो कार्य हो रहे है उनका लाभ नीचे के स्तर के लोगो को पहुंचा है। हर गांव में निर्माण और विकास की छाया पडी है। सरकार ने योजना को जिला स्तर पर अर्थपूर्ण बनाने के लिए योजना का विकेन्द्रीयकरण किया है। एक वि ोश उपलब्धि जो कि पूरे दे ा में केवल हमारी सरकार ने और हमारे मुख्य मंत्री ने किसान के लिए दी हे वह है 113 करोड रुपए पक्की नालियां का कर्जा जो किसानो के जिम्मे था, वह माफ किया है। यह बहत प्र ांसनीय कार्य है। दूसरा प्र ांसनिय कार्य जो इस सरकार ने किया है वह है किसानो का मालिया माफ करना। यह मालिय टोडरमल के जमाने से चला आ रहा था लेकिन इस सरकार ने एक ही कलम से इसे माफ कर दिया। ऐसा करके सरकार ने पूरे हिन्दुस्तानं में एक मिसाल कायम की है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ प्रकृति का प्रकोपा भी आता रहता है जिस पर किसी का जोर नही। अभी पिछले सप्ताह सात जिलो में बडी भारी ओलावृश्टी हुई। उपाध्यक्ष महोदय, आज के समाचार पत्र में छपा है कि

सरकार ने चार करोड रुपया ओलावृश्टी से हुई हानि के लिए रखा है और एक समिति भी बनाई है जो नुक्सान का जायजा लेगी। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। (**इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए**) अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस दि ाा में इतनी जल्दी फैसला लिया है, यह बहुत ही अच्छा कदम है। सरकार का प्रयत्न है कि सभी वर्गो को समान अधिकार मिले, समान न्याय मिले और काम के उचित अवसर मिले, इसके लिए सरकार भूरी भूरी प्र ांसा की पात्र है। पिछडे वर्ग के लोगो के लिए सरकार ने एक वि ोश प्रावधान किया है कि 50 अथवा 50 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में पिछडे वर्गो का एक नम्बरदार नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी पंचायत में पिछडे वर्गो का कोई प्रतिनिधि नही है और गांव में पिछडे वर्गो की आबादी दो प्रति ात से अधिक है तो उस में एक सदस्य पिछडे वर्ग का नियुक्त किया जाएगा, ऐसा करके सरकार ने पंचायत के अन्दर पिछडे वर्ग के लोगो को प्रतिनिधित्व दिया है। जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोगो का भाामलात भूमि के अन्दर हक रखा है उसी तरह से पिछडे वर्ग के लोगों को यह सम्मान देकर, समान दर्जा देकर हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हैं समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य बंधुत्व लाने की दि ाा में सरकार की ओर से किया गया यह एक सराहनीय कदम है।

गृह मंत्री (चौधरी तैय्यब हुसैन): मोहतरिम स्पीकर साहब, वैसे तो सी0 एम0 साहब ने बोलना है लेकिन मै ज्यादा वक्त नही लूंगा। एक मुअजिज मैम्बर ने एक कत्ल के बारे में यहां जिक्र किया। मै समझता हूं कि उन्होने वाकयात से हटकर बेबुनियाद बात की है। स्पीकर साहब, वाक्या यह है कि रात को ट्रक आ रहा था। पुलिस पार्टी ग त पर थी। पुलिस पार्टी ने ट्रक को रुकने का इ ारा किया लेकिन ट्रक नही रुका। पुलिस ने ट्रक पर गोली चलाई। गोली छोटल्ली के सरपंच को लगी जिसमें उसकी मौत हो गई। दूसरे दिन इंट्रेस्टिड लोगो ने थाने पर हमला किया और वहां पर थाने की जीप को जला दिया। उन लोगो के खिलाफ केस दज्र कर लिया गया है और इंक्वायरी की जा रही है। स्पीकर साहब, जिस सिपाही की गोली से सरपंच मारा गया उसको गिरफतार किया गया है और उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ए0 एस0 आई0 जो पुलिस पार्टी का इन्चार्ज था और एस0 एच0 ओ0 को सस्पैंड कर दिया गया था। स्पीकर साहब, इससे ज्यादा जल्दी और मुनासिब कार्यवाही और क्या हो सकती है? जो सम्भव था वह हमने कर दिया। जो कुछ मैम्बर साहब ने कहा है मै समझता हूं कि वह वाकयात के खिलाफ है। स्पीकर साहब, मै खुद उस गांव मे गया। सरकार को उस परिवार के साथ पूरी हमदर्दी है। सरकार ने दस हजार रुपए की ऐक्सग्रे ि ाया ग्रांट उस परिवार का दी हैं। उस परिवार का जो सबसे बडा बच्चा है ओर जो अपाहिज है उसके लिए भी को ि ा ा की जा रही है कि उसको कहीं नौकरी पर लगाया जाए।

बेबुनियाद बात कहकर मगरमच्छ के आंसू बहाने से मै ंनही समझता कि यह उस परिवार के साथ हमदर्दी की बात है और कोई मुनासिब बात है। मै बस इतना ही कहना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): स्पीकर साहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर दो रोज से बहस चल रही हैं माननीय मैम्बर्ज़ ने बहुत सी बातें इस बारे में कही है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते है कि जब 1966 में हमारी स्टेट बनी थी तो वह बहुत बैकवर्ड स्टेट थी और उस समय लोगो का यह सवाल था कि भाायद हरियाणा प्रदे ा अपने मुलाजिमो की तनखवाह भी न दे सके लेकिन हरियाणा बनने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय प्राईम मिनिस्टर थी, ने हमारी बहुत सहायता की। कोई भी प्रदे ा अपने पैसे से अपने प्रदे ा की तरक्की नही कर सकता। उसे दिल्ली की सरकार से माली सहायता की जरुरत पडती है। उनकी माली सहायता से हमारे प्रदे ा ने तरक्की के काम किए। जब हमारा प्रदे ा 76 लाख की आबादी का प्रदे ा था तो हम खाने के लिए अनाज पैदा नही कर पाते थे। उस समय एक लाख टन अनाज हम हर साल दिल्ली सरकार से लेते थे लेकिन आज जब खाने वालो की तादात 1 करोड 30 लाख हो गई है, इसके बावजूद भी हम 30–35 लाख टन अनाज दिल्ली की सरकार को दूसरे प्रदे ाो के लिए देते है। इस तरह हमने पहले से बहुत तरक्की की है। जिस समय हरियाणा प्रदे ा अलग बना तो उस समय हमारे प्रदे ा में बिजली की पर कैपिटा कंजम्प ान केवल

57 यूनिट्स थी और अब यह बिजली की कंजम्प ान बढकर पर कैपिटा 234 युनिट्स हो गयी है। इस साल हमारा अन्दाजा है कि यह फिगर बढकर 270 युनिटस तक पहुंच जाएगी। इसमें भी हमने तरक्की की है। स्पीकर साहब, इरीगे ान का जहां तक सवाल है, जब हमारा प्रदे ा पंजाब से अलग हुआ तो उस समय 12 लाख 95 हजार हैक्टेयर जमीन सैराब होती थी और 1975–76 में यह फिगर 16 लाख 78 हजार हैक्टेयर हो गयी। स्पीकर साहब, यह बडे ताज्जुब की बात है कि जनता पार्टी के राज में, जब चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे, 16 लाख 78 हजार से घटकर यह फिगर 16 लाख 59 हजार रह गयी। ये फिर किस मुहं से किसानो के हमदर्द बनने की बात करते हैं? इरीगे ान तो उन्होने घटा दिया। इस पर कोई जोर नही दिया और अब यह फिगर 1985–86 मे बढकर 19 लाख 45 हजार हैक्टेयर हो गयी। उनके पहले और उनके बाद में हरियाणा मे तरक्की हुई लेकिन चौधरी देवी लाल जी के काल में इरीगे ान घट गई। इसके अलावा जनता पार्टी के राज में इरीगे ान की टोटल 28 स्कीमें बनी, जिससे केवल 91 किलोमीटर्ज़ की माईनर्ज़ बनाने की स्कीमज़ मंजूर हो गयी थी। वे सिर्फ 38 लाख 50 हजार रुपए की लागत से बनी। इससे बडी बात और क्या हो सकती है कि एक आदमी दो अढाई साल के अपने राज में किसानो के लिए 38 लाख 50 हजार रुपए से ज्यादा इरीगे ान के उपर खर्च न कर सका हो। उनके बाद 129 स्कीमज़ मंजूर की गई जिनके उपर 15करोड 50 लाख रुपए की लागत आयी। तो यह कांग्रेस सरकार ने ही तरक्की की है और लोकदल

के साथी जो किसानो के बारे में डींग मारते है उन्होने तो केव किसानो का नुकसान ही किया है। दूसरी तरफ बिजली के बारे में भी जहां पर वे भाशण देते है, यह कह देते है कि मेरे वक्त में बिजली जनरे ान इतनी थी। बिजली की जनरे ान हरियाणा प्रान्त में, जब हरियाणा प्रान्त अलग से बना तो 343 मैगावाट थी और 31–3–1977 तक यह कैपेसिटी बढकर 606 मैगावाट हो गयी। चौधरी देवी लाल जी के भाासन में सिर्फ डेहर के पावर हाउस से, जो पहले से ही बन रहा था और जो दिल्ली की सरकार ने बनवाया था, 146 मैगावाट बिजली आई, जिसमें हरियाणा सरकार का कोई हाथ नही था। इसके अलावा एक युनिट भी पावर जनरे ान नही बढायी। अब यह 343 मैगावाट से बढकर 1536.5 मैगावाट हो गयी है। यह सब कुछ कांग्रेस सरकार की बदौलत ही हुआ है।

स्पीकर साहब, अब मैं टयूबवैल्ज कनेक ान के बारे में बता दूं। जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी, उस समय केवल 20–22 हजार के करीब टयूबवैल कनेक ान दिए गये थे और कांग्रेस सरकार के वक्त में 31–3–1986 तक इन टयूबवैल्ज की तादाद बढकर 2 लाख 77 हजार 327 हो गयी थी। इसी तरह से इंडस्ट्रियल कनैक ानज़ की तादाद बढ 9749 से 54537 हो गई। जनरल सर्विस कनैक ानज् उस वक्त, जब हरियाणा बना, 2 लाख 81 हजार 778 थे और 31–3–1986 को इनकी संख्या बढकर 13 लाख 89 हजार 282 हो गयी। तो इस तरह से बिजली की

कमी जो आज कम महसूस की जाती है कि हमारी खपत बहुत बढी है। कहां 57 यूनिट पर कैपिटा और कहां आज 270 युनिट के करीब पर कैपिटा कंजम्प ान है। पहले कंजम्प ान कितनी थी और आज कितनी है। पहले टयूबवैलज के कनैक ान कितने थे और आज कितने हो गये है। पावर जनरे ान जितनी कांग्रेस सरकार के भाासन में हरियाणा में बढी यह एक खास रिमार्केबल बात है। कहां 343 मैगावाट फिगर जो आज 1556.5 मैगावाट तक पहुंच गयी। इसके अलावा डिस्ट्रिब्यू ान आफ फार्मर्ज़ टयूबवेलज कनैक ान तथा बिजली के दूसरे कामो मे हमने बेहद तरक्की की है। दूसरी बात एक और है कि किसानो को नहर का पानी देने के लिए माईनर्ज़ भी बढवानी पडती है, डिस्ट्रिब्यूटरीज भी नयी बनानी पडती है लेकिन चौधरी देवी लाल जी के भाासन काल में यह आदे ा हुए कि अगर किसार कि एक बुर्जी माईनर बनाी जाएगीतो उस माईनर की कीमत और ब्याज दोनो ही किसान से वसूल किये जाएंगे। जो आज किसानो की भलाई की दुहाई देते है, यह हुक्म उनके ही काल का था। इसके अलावा 113 करोड रुपया जो किसान की तर वाटर कोंर्सिज की लाइनिंग का कर्जा बाकी था, वह भी हमने कतई तौर पर माफ कर दिया है। (तालियां) इतनी ही नही, अब हमारे पास किसानो की तरफ से मांग आ रही है कि हमारी खालें पक्की करो। जब उनको पैसा देना होता था तो खालें कम बनवाते थे लेकिन अब उनकी मांग ज्यादा आ रही है कि खालें पक्की की जाएं। तो अब यह रुपया कई सौ करोड में जाएगा, जो हमने माफ किया है, इससे किसानो को अब बहुत ही

ज्यादा फायदा होगा। पक्की खालें बनने से पानी की सीपेज बचेगी, जो जमीन सीपे से कल्चर हो जाती थी, अब उसका बचाव होगा और किसान के लिए पानी भी बचेगा।

स्पीकर साहब, आगे मै एस0 वाई एल के बारे में भी स्थिती स्पश्ट करना चाहता हूं। 1985 में प्रधान मंत्री महोदय और संत हरचन्द सिंह लौंगोवाल जी के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौते मे एक क्लाज प्रधान मंत्री जी ने यह रखी कि पंजाब की सरकार, पंजाब के हिस्से में एस वाई एल के भाग को एक साल के अन्दर बनायेंगी। मै इस बात को मानता हूं कि वह नहर एक साल के अन्दर अन्दर नही बनी और इसकी हमको चिन्ता है कि वह नहर क्यों नही बनी? जिस तरह से हमको इसकी चिंता है उसी तरह से महारे प्रधान मंत्री जी को भी इस बात की चिन्ता है कि यह नहर एक साल में बनकर तैयार क्यों नही हुई और दिल्ली की सरकार बार बार इस की प्रोग्रेस को मोनीटर करती है। हम यह चाहते है और हमारी ह मांग भी बराबर बनी हुई है कि दिल्ली की सरकार एस वाई एल के काम को टेक ओवर करकू जल्द से जल्द इसको बनाकर के दे लेकिन हमारे इस रास्ते में रोडे अटके। पिछले दिनों लोकदल की तरफ से चौधरी देवी लाल जी की तरफ से तीन आदमियों का एक प्रतिनिधि मण्डल एस वाई एल नहर को देखने के लिए पंजाब गया, जिसमें श्री औम प्रका ा बेरी, चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल और तीसरे श्री महे ा भार्मा थे। उन्होने आ करके चण्डीगढ में प्रैस को एक ब्यान दिया कि एल वाई एल का

काम बडी तेजी से चल रहा है, उसको दिल्ली की सरकार को अपने हाथ में लेने का कोई औचित्य नही है। उन्होने कहा कि अगर दिल्ली की सरकार उसको अपने हाथ में ले लेगी तो नहर धीरे बनेगी, अब यह नहर तेजी से बन रही है। लोकदल के डलीगे ान पर एक मैम्बर ने यह लिखित ब्यान प्रैस को दिया जिसको चौधरी देवी लाल ने वहां भेजा था। फिर वे कहते है कि इसमें हरियाणा का भला होता है। चौधरी देवी लाल जिस समय मुख्य मंत्री थे उन्होने एस वाई एल को बनाने की तरफ कोई कदम नही उठाया। फिर वे आज क्या करते है कि देहातों मे जाते है और एस वाई एल की दुहाई देते है, उसके नाम से नारा लगाते है। दो–ढाई करोड रुपया चन्दा इकट्ठा करके भी खा गए। तो जो आदमी ऐसी दुहाई दे, प्रदे ा के किसानो के हितो के खिलाफ काम करे, इस बात का हमें बडा अफसोस है। दिल्ली की सरकार से हमारी मुतबातर एक मांग है ि कवह एस वाई एल को टेक ओवर करके इसे जल्द से जल्द बना कर तैयार करें क्योंकि हम एस वाई एल की कंस्ट्रक ान की प्रोग्रेस से संतुश्ट नही है। अलबत्ता उसका 78 फिसदी अर्थ वर्क पूरा हो चुका है, 20 फिसदी लाइनिंगा का काम पूरा हो चुका है और कुछ पुल भी बन चुके है मगर बहुत से पुल बनने है और क्रास ड्रेनेज वर्क होने है। उनके उपर जो प्रोग्रेस है, उससे हम संतुश्ट नही है। हम चाहते है कि दिल्ली की सरकार इसको जल्द से जल्द लेकर हमारे लिए एस0 वाई0 एल0 जल्दी से तैयार करे ताकि हरियाणा के किसानो के खेत में पानी पहुंचे। हम प्रधान मंत्री जी के बडे आभारी है

जिन्होने एस0 वाई0 एल0 का पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार के सिर पर ले लिया। हमारी इतनी क्षमता नही थी, हमारी इतनी कैपेसिटी नही थी, हमारे पास इतना धन नही था कि हम उस पर खर्च कर सकते। तो प्रधान मंत्री जी ने यह पैसा, यह खर्च दिल्ली की सरकार पर डाल कर हमारे ऊपर एक एहसान किया है, हमारे ऊपर मेहरबानी की है, इसके लिए हम उनको म ाकूर है। इसके अलावा एक बात लोकदल वाले खास तौर से चोधरी देवी लाल कहते है कि अगर मै मुख्य मंत्री बन गया तो बैंको का कर्जा माफ कर दूंगा। स्पीकर साहब, आप जानते है, मै भी जानता हूं और पूरा सदन भी इस बात को जानता है कि देवी लाल एक अनपढ आदमी है। अनपढ आदमी कोई भी गैर–जिम्मेदारी की बात कह सकता हैऔर यह कहना कि बैंको के कर्जे माफ कर दूंगा, यह बिल्कुल गैर–जिम्मेवारी की बात है। सरदार लछमन सिंह ने अपनी तकरीर में बताया कि बैंको के कर्जे कैसे माफ कर देंगे? और फिर किसी भी मुख्य मंत्री को या किसी भी सरकार को यह क्या अधिकार है कि वह बैंको का कर्जा माफ कर दें। यह उनका गरीब लोगों को, प्रदे ा के सीधे सादे और भोले भाले आदमियों को बहकाने का तरीका है। मुझे अफसोस है कि एक आदमी जो दो साल तक मुख्य मंत्री रह चुका, वह इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करता है। अगर बैंको का कर्जा कोई मुख्य मंत्री माफ कर सकता होता तो दो साल चौधरी देवी लाल मुख्य मंत्री रहे, वे माफ क्यो नही कर गए? जो 113 करोड रुपया आज की कांग्रेस सरकार ने, मेरी सरकार ने वाटर कोर्सिज का माफ कर दिया, चौधरी देवी

लाल ने यह भी नही किया। उल्टा एक बुर्जी अगर माइनर बनी तो उसका ब्याज समेत रुपया किसान से वसूल करने का हुकम दे दिया। इतने हमदर्द वे किसान के हैं। इसके अलावा जमीन के मालिए की भी माफी कांग्रेस सरकार ने की है। कुर्सी पर थे उस वक्त तो अपने कुनबे का पेट भरने को लगे रहे। बडी धन दौलत बनाई, बडी रि वत खाई। आपको याद होगा, स्पीकर साहब, चौधरी देवी लाल ने मेरे खिलाफ एक करप् ान का केस रजिस्टर करवाया था। वह केस इसलिए रजिस्टर नही करवाया कि मै कपट था बल्कि इसलिए किया कि 285 बनियों की तला ाी करवा कर, थाने में बुला कर देवी लाल और इसके लडको ने उनसे रि वत लेकर उनका पीछा छोडा। उन्होने अपना घर बनाने के लिए केस रजिस्टर करवाया था। पैसा बनाने में जितना माहिर देवी लाल और उनका कुनबा है उतना कोई हो नही सकता। तीन पीढी उसकी चन्दा इकटठा करके खाती है। उसके कुनबे का कोई आदमी पढा लिखा नही है। अगर वह बैंको का कर्जा माफ कर सकता था, तो वह दो साल मुख्य मंत्री रहा कर गया होता। आज उसको किसान की बात कैसे याद आई। जब मुख्य मंत्री था तब तो किसान की कोई बात उसे याद नही आई। इसके अलावा एक बात चौधरी देवी लाल कह देते है कि अगर मै मुख्य मंत्री बन गया तो मै बूढो की पैन् ान कर दूंगा, अपाहिजो की पैन् ान कर दूंगा और विधवाओं की पैन् ान कर दूंगा। स्पीकर साहब, इससे ज्यादा ना समझी, बे समझी और गैर–जिम्मेदाराना बात कोई क्या कर सकता है। बूढे आदमियो की पैन् ान 1969–70 मे मैने भाुरु कर दी थी और आज

1986–87 में हरियाणा प्रदे ा में 39558 आदमियों को ओल्ड एज पैंन ान दी जा रही है। हैंडीकैप्ड के लिए वह कहता है कि मै पैं ान कर दूंगा, विडोज़ और डिस्टीच्युट वीमैन के लिए कहता है कि मै पैंन ान कर दूंगा। स्पीकर साहब, इस आदमी को यह नही पता कि इन सभी की पैन ान 1981–82 मे चौधरी भजन लाल कर गए थे। बूढो को 17–18 साल से पैन ान मिल रही है और बाकियों को पिछले 6–7 साल से मिल रही है। वह कहता है मै पैन ान कर दूंगा, तो इससे ज्यादा गैर–जिम्मेदारी की बात, लोगों का बहकाने की बात और क्या कही जा सकती है? 1986–87 मे 7172 हैंडिकैप्ड आदमियों को, 9704 विडोज़ और डिस्टीच्यूट को और 5704 डैस्टीच्यूट चिल्ड्रन पैन ान मिल रही है। कुल मिला कर स्टेट में61836 आदमियों को पैन ान हम आज दे रहे है और दिन प्रति दिन इसकी तादाद बढती जा रही है। फिर भी अफसोस की बात है कि एक आदमी जो कहे की मै भावी मुख्य मंत्री हूं। लेकिन देवी लाल का एक लडका चौधरी प्रताप सिंह जो भूतपूर्व विधायक है, **12:00 बजे** कहता है कि मै तो अपने पिता जी को भूतपूर्व मुख्य मंत्री भी नही मानता क्योंकि जब देवी लाल मुख्य मंत्री थे तो राज तो उस समय मेरा भाई औम प्रका ा किया करता था और चौधरी देवी लाल तो दखल दिया करते थे। अब वे लोगों के सामने कह रहे है कि मै भावी मुख्य मंत्री हूं। यह बडे अफसोस की बात है कि ऐसे आदमी हरियाणा की राजनिती में हैं। स्पीकर साहब, वैसे भी वे आज तक किसी का बन कर के नही रहें हैं। एक बडी मिसाल चौधरी देवी लाल जी के बारे में ये है कि यदि

कोई उनका भला करता है तो वे उसका बुरा करते हैं। एक दफा सरदार प्रताप सिंह कैरों ने चौधरी देवी लाल को प्रदे ा कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। इस पर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री धेबर भाई ने कहा िकमे ऐसे डकैत को पी0 सी0 सी0 का प्रजीडैंट नही बनने दूंगा। उसके बाद उन्होने चौधरी देवी लाल का इस्तीफा मांग कर उन्हे चलता कर दिया। फिर सरदार प्रताप सिंह ने एक बार देवी लाल को पार्लियामैंट सैक्रेटरी बना दिया। उसके बाद फिर चौधरी देवी लाल ने उनकी ही इज्जत पर हाथ डाला। जब मै 1968 में मुख्य मंत्री बना तो चौधरी देवी लाल जी मेरे पास आये और बोले कि मै तंग हो गया हूं, मेरी कुछ सहायता करो। मैने कहा चौधरी साहब आप तो अनपढ हो, मै आपको कहां लगाऊं? इस पर वे कहने लगे कि मेरी रोटी का साधन करो। मैने उनको खादी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। इस पद पर वे तीन साल तक रहे। उसके बाद उसने मेरे साथ जो कुछ किया है वह सब को पता है। बाद में फिर चौधरी चरण सिंह ने उनको राजनिती में जिंदा किया। फिर देवी लाल चौधरी चरण सिंह पर बेईमान होने का इल्जाम लगाया। चौधरी चरण सिंह पर आज तक हिन्दुस्तां मै किसी भी आदमी ने बेईमान होने का इल्जाम नही लगाया लेकिन चौधरी देवी लाल उन पर यह आरोप भी लगाया। अभी भी चौधरी देवी लाल ने चौधरी चरण सिंह को माफ नही किया है। अब देवी लाल उनकी अगली पीढी से बदला लेने में लगे हुए हैं। अब उन्होने उनके लडके चौधरी अजीत सिंह की इज्जत पर हाथ डाला है। मै यह बात भी आपके जरिए जनता

को समझाना चाहता हूं कि अगर जनता उसका साथ देगी तो वह जनता की इज्जत पर भी हाथ डालेगा। वह किसी को माफ करना नही जानता। उसकी यह एक परमानैंट क्रिमिनल टैन्डेन्सी हैं।

स्पीकर साहब, मै यह बतला रहा था कि हमारे प्रदे ा ने कांग्रेस के भाासन काल मे बहुत तरक्की की है। हरियाणा प्रदे ा जो तरक्की के मामले में 11वें स्थान पर था अब दूसरे नम्बर पर है।

स्पीकर साहब, अभी इसी महीने पिछले दिनो बैकवर्ड क्लासिज की एक कांफ्रैस पानीपत में हुई थी। वैसे तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने आल इंडिया बेसिज पर हरिजनो और बैकवर्ड क्लासिज के लिए काफी कुछ किया है और आगे भी उनके लिए कुछ करना चाहती है क्योंकि यह उनका हक बनता है। ये भाई कांग्रेस के राज में भाोशित रहे है, दबे हुए रहे हैं। उनको सोसायटी में बराबर के अधिकार नही थे, इसलिए उनके लिए कुछ करना निहायत जरुरी था। अब जिस गांव मे बैकवर्ड क्लासिज की आबादी 2 प्रति ात की होगी, वहां से एक नम्बरदार उनकी जाति का बना देंगे। इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि जिस गांव की पंचायत में बैकवर्ड पंच चुन करके नही आयेगा वहां पर एक पंच बैकवर्ड क्लासिज का कोआप्ट कर देंगे। मैंने कांफ्रैस के दौरान तो इस बात का ऐलान नही किया था मगर बाद में हमने फैसला कर लिया कि ब्लाक समिति के लेवल पर भी अगर बैकवर्ड क्लासिज का कोई प्रतिनिधि चुन करके नही आयेगा तो ब्लाक

समिति के अन्दर भी प्रतिनिधि उनका कोआप्ट कर देंगे। इसके अलावा भाामलात देह की जो जमीन है वह 33 परसैन्ट हरिजन भाइयों को दी जाती है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि इसमें से 10 परसैंट जमीन बैकवर्ड क्लासिज के भाइयों को भी दिया करेंगे। इसके लिए कानून मे तबदीली करने के लिए एक बिल इसी सै ान में ला रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ मांगा था ओर कोई मांग आयेगी उसकी लिए मैने 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। इस कमेटी के अध्यक्ष हमारी प्रदे ा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री हरपाल सिंह होंगे। इस कमेटी के फाइनैंस मिनिस्टर, सो ाल वैल्फेयर मिनिस्टर और प्रत्येक जिले में एक एक बैकवर्ड क्लास का आदमी, मैम्बर होंगे। इस कमेटी के कुल 15 सदस्य होंगे। 15 आदमियों की यह कमेटी फैसला करेगी कि बैकवर्ड क्लासिज के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। सरकार बैकवर्ड क्लासिज के लिए और हरिजन भाइयों के लिए जितना कर सकती है उतना करने की कोि ा ा करेगी। हमारी पूरी कोि ा ा होगी कि सोसायटी में उन्हे सही स्थान मिले और सब के सब बराबर हो, किसी से कोई अपने आप को इन्फीरियर न समझे। हमारी यह भरपूर कोि ा ा हेागी कि बैकवर्ड क्लासिज के भाई और हरिजन भाई सब के साथ बराबर सीने से सीना तान कर चलें।

स्पीकर साहब, हरियाणा प्रदे ा में एक ही मैडिकल कालेज रोहतक में है। पहली बार जब मै मुख्य मंत्री था तो उस

वक्त मेरा इरादा था कि उसे लाईफ साइंस युनिवर्सिटी बनाया जाये। मगर बाद में मेरे सक्सैसर्ज़ ने फैसला बदल दिया और उसे एक जनरल युनिवर्सिटी बना दिया। इस मैडिकल कालेज रोहतक की तरफ कभी किसी का ध्यान उतना नही गया जितना जाना चाहिए था और उसका नतीजा यह हुआ कि मैडिकल कालेज का स्टैंडर्ड गिर गया। अब हमने यह तय किया है कि मैडिकल कालेज रोहतक का स्टैण्डर्ड आल इंडिया मैडिकल इंस्टीच्यूट और पी0 जी0 आई0 से कम का न हो, उनके मुकाबले का हों। हमने वहां के लैक्चररज, रीडर्ज, असिस्टैंट प्रोफेसर और डायरैक्टर व प्रिंसिपल आदि तनखवाहे ग्रेड बढा दिये है। मैडिकल कालेज में प्राइवेट वार्ड के 50 कमरे है। 50 कमरे और बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। ि ालान्यास कर दिया गया है और काम जारी है। फिर जो लोग मरीजों के साथ आते है उनको ठहरने में बडी तकलीफ होती है। उनके लिए दो करोड रुपये की लागत से हम एक ऐसी धर्म ाला बना रहे है जिससे कम से कम 750 आदमियों के रहने के लिए जगह हो। इसके अलावा मैडिकल कालेज के लिए पूरी बॉडी की स्कैनिंग के लिए 3 करोड 35 लाख रुपये की म ीन देने का प्रधान मंत्री जी ने वायदा किया है। प्रधान मंत्री जी ने हमें सहायता दी है वह रुपया हमने उसमें से उनका इयर मार्क कर दिया है। इसके साथ साथ प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा है कि जैसे लखनऊ के संजय मैमोरियल इंस्टीच्यूट को जापान से करीब 20 करोड रुपए का इक्विपमैंट मिलेगा उसी तरह का इक्विपमैंट किसी दूसरे बडे मुल्क से डोने ान के रुप में रोहतक मैडिकल

कोलज को दिलाएंगे। तो अध्यक्ष महोदय, आने वाले 2–3 साल के अन्दर उसी तरह का 20–25 करोड रुपए का इक्विपमैंट रोहतक मैडिकल कालेज को भी आएगा, यह प्रधान मंत्री जी ने फैसला किया हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे मैडिकल कालेज का स्टैन्डर्ड खासा ऊंचा हो, वह हिन्दुस्तान के किसी इंस्टिच्यूट से नीचे न रहे बल्कि ऊंचा रहे। यही हमारी भरकस कोि ा ा है।

स्पीकर साहब, अब मैं ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीमज के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। हमारे प्रदे ा में 5290 प्रोब्लम विलेजिज थे। इनमें से 31 मार्च, 1986 तक 3962 कवर हो गए थे। इस साल हमारा इरादा 480 प्रोब्लम विलेजिज को कवर करने का है। बाकी 848 प्रोब्लम विलेजिज रह जाएंगे। 396 नए प्रोब्लम विलेजिज बनने वाले हैं। इस तरह से कुल 1244 प्रोब्लम विलेजिज कवर करने को रहते है। हमारा प्रोग्राम है कि वर्श 1987–88में 440, वर्श 1988–89 में 440 और वर्श 1989–90 तक हर गांव को पीने का अच्छा पानी दे देंगे। यह बहुत बडी अचीवमैंट है। जहां तक भाहरो मे पीने के पानी की तकलीफ का संबंध है उसे भी हम धीरे धीरे दूर करते जा रहे है। बहुत से भाहरो में पीने के पानी की तकलीफ है। हमने यह मामला हिमाचल प्रदे ा गवर्नमैंट के साथ टेक–अप किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इस मसले को जल्दी ही हम हल कर लेंगे।

स्पीकर साहब, हम वीकर सैक ान्ज को हुडडा की तरफ से 80 रुपये गज की हिसाब से प्लाट बना कर दे रहे है। 4607

प्लांटस में से कुछ प्लांटस तो अलौट हो गए है और कुछ इस साल के अन्त तक कर देंगे। बहुत सी जगह पर हुडडा कालोनियां बना बना कर वीकर सैक ान को प्लाट देने का प्रोग्राम में लगा हुआ है। इसमें हुडडा बहुत कामयाब है।

स्पीकर साहब, जहां तक सडको की बात है, मोरनी हिल्ज के कुछ गांव, खादर एरिया के कुछ गावं, जहर का नाला और जमुना नदी के बीच के कुछ गांव और फरीदाबाद तथा दिल्ली के आस पास के थोडे से गावों को छोडकर बाकी हर गांव तक पक्की सडक पहुंच गई है। स्पीकर साहब, जिन सडको को मै यहां से जाने से पहले बना गया था, उनकी बादमें मरम्मत नही हुई। उनकी मरम्मत के लिए पैसा भी नही था। अब प्रधान मंत्री जी ने जो 403 करेाड रुपया दिया है उसमें से हम 31 मार्च, 1987 तक पांच करोड रुपया देहात की सडको की मुरम्मत पर लगाना चाहते हैं। यानी यह पैसा स्टेट हाई–वेज़ और ने ानल हाई–वेज पर खर्च नही होग बल्कि देहात की सडको पर खर्च होगा। अगले साल हम इससे भी ज्यादा सडको की मुरम्मत करना चाहते है। इसके अलावा, जहां जहां बहुत जरुरी है नई सडके भी हम बनाने की कोि ा ा करेंगे।

स्पीकर साहब, हमारा हरियाणा प्रदे ा सबसे पहला प्रदे ा है जिसने सैन्ट्रल फोर्थ पे कमी ान की सिफारि ाों को माना है। इससे हमारे मुलाजिमो की तनख्वाहे बढेगी, मगर अफसोस के साथ कहना पडता है कि कुछ मुलाजिम विरोधी

राजनैतिक पार्टी के कहने पर ऐजीटे ान की बात करते है, लेकिन वे धाखे में हैं। वे समझते है कि इलैक ान नजदीक है इसलिए भाायद उनकी नाजायज बातें भी मानी जाएंगी। स्पीकर साहब, मै आपके जरिए यह बात साफ करना चाहता हूं कि इलैक ान की वजह से मेरी सरकार किसी ऐम्पलाई के सामने झुकेगी नही। हर जायज बात हम मानेंगे। जो जायज बात हे वह देंगे। फोर्थ पे कमी ान की रिपोर्ट में जहां ऐडजस्टमैंट होनी है उसके लिए चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैन ाप में हमने एक कमेटी बना दी है जो जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी। फोर्थ पे कमी ान की सिफारि ाों के अनुसार तनख्वाह 1–1–1986 से देने का निर्णय किया गया है लेकिन 1अप्रैल, 1987 में बढोतरी कै ा में देंगे। कुछ लोग अपोजी ान पार्टी के कहने पर इसके खिलाफ भी ऐजीटे ान जैसी बातें करते है। मगर सरकार टस से मस नही होगी। अगर कोई ऐजीटे ान करके सरकार को झुकाने की बात सोचता हो तो यह उसकी गलती है। सरकार इस मामले में झुकेगी नही। झुकेगी सरकार नही कि जो ऐम्पलाइज को देना चाहिए, जो उनका हक बनता है, उससे ज्यादा उनको दे दिया है।

इसके अलावा स्पीकर साहब, प्रधान मंत्री जी ने जो 403 करोड रुपया दिया है उसमें से जैसा मैने पहले बताया हरिजन चौपालो के लिए 1 करोड इयर मार्क किया गया है। 30–35 लाख रुपया बैकवर्ड क्लासिज की चौपालो के लिए दिया गया है। 5 करोड रुपया सडको की मुरम्मत के लिए दिया गया है। दो–ढाई

करोड रुपया उन म्यूनिसिपैलिटीज को दिया गया है जिनकी हालत खराब है, जहां सडके टूटी हुई है, लाईट का प्रबन्ध नही है, पीने के पानी देने के लिए नालियां बिछाने के लिए नही है। जो म्यूनिसिपल कमेटीज 31 मार्च तक रुपया खर्च कर लेंगी और उनकी मांग जायज होगी उनको हम फिर रुपये देंगे।

स्पीकर साहब, एक अच्छी बात हमने और की है। किसान को सबसे बडी तकलीफ तब होती है जब नहर तो चलें लेकिन पानी टेल तक न पहुंचे। आप तो खुद इरीगे ान एंड पावर मिनिस्टर रहे हैं और आप जानते है कि किसान की क्या हालत होती है जब टेल पर पानी नही पहूंचता है। हमने यह फैसला किया है कि प्रधान मंत्री जी ने जो 403 करोड रुपये की सहायता दी है उसमें से 10 करोड रुपया इस काम के लिए इयर–मार्क कर दिया जाए। रुपया रिलीज भी कर दिया है ताकि जल्दी से जल्दी हरियाणा के किसान के खेत को नहर के टेल के जरिए भी पानी पहुंच जाए। यह अगर हम कर पाए तो बहुत बडी अचीवमैंट होगी और मेरा ख्याल है कि इसमें हम कामयाब होंगे। हमारे सिंचाई मंत्री जाकर खुद भी मौका देखते है और लोगो की बात भी सुनते है। हम इस बारे में पूरी कोि ा ा कर रहे है। स्पीकर साहब, प्रधान मंत्री जी ने हमको 403 करोड रुपया दिया उससे हमारी स्टेट की माली हालत एक दफा बन गई, हमको सांस आ गया मगर स्पीकर साहब, मुझ अफसोस भी है और ताज्जुब भी है कि विरोधी पार्टी के नेता चौधरी देवी लाल इस पैसे के बारे में कुछ

और ही कहते है। 17 दिसम्बर को प्रधान मंत्री जी ने पलवल में 403 करोड रुपए देने का ऐलान किया और छः जनवरी को चौधरी देवी लाल ने इलैक ान कमी ान को चिटठी लिख दी कि प्रधान मंत्री जी ने यह गलत काम किया है। हरियाणा को फायदा हो और उसके बारे में भी चौधरी देवी लाल जी यह कहें कि यह गलत काम किया है तो इससे बडी अफसोस और दुःख की कोई और बात नही हो सकती। हरियाणा का इनसे बडा विरोधी, इनसे बडा दु मन कोई और आदमी हो नही सकता जो हरियाणा के हितो के भी ख्याल न रखता हो।

स्पीकर साहब, मै समझता हूं कि एस0 वाई0 एल0 को केन्द्र सरकार टेक–ओवर कर लेगी। केन्द्र सरकार से हमारी यह बार बार प्रार्थना रही है और अब भी हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे एस0 वाई0 एल0 को अपने हाथ में ले लें। स्पीकर साहब, साथ साथ मैं यह श्रसर कहूंगस कि जैसे ही हम 403 करोड रुपया खर्च कर देंगे उसके बाद प्रधान मंत्री जी हमें और पैसा भी दे देंगे ऐसी मैं आ ाा रखता हूं। हम उनकी सहायता से दो नम्बर से एक नम्बर पर छलांग लगा कर पहुंच जायेंगें। इन भाब्दो के साथ मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि गवर्नर साहब के धन्यवाद के लिए जो मो ान चौधरी ई वर सिंह जी ने रखा हे उसे पास किया जाये।

राज्यपाल के अभिभाशण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर मतदान

श्री अध्यक्षः अब मै मो ान पुट करता हूं।

प्र न है–

'कि गवर्नर साहब को एक ऐड्रेस फौलोंइंग टर्म्ज़ में प्रेजैन्ट किया जाये–

'कि इस सै ान में असैम्बल हुए हरियाणा विधान सभा के मैम्बर्ज उस एड्रेस के लिए गवर्नर साहब के डीपली ग्रेटफूल है जो उन्होने 23 फरवरी,1987 को हाउस में डिलिवर करने की कृपा की है'।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वर्श 1981–82 और 1982–83 की ऐक्सैस डिमान्डज ओवर ग्रान्टस एंड ऐप्रोप्रिए ांज पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः अब ईयर 1981–82 और 1982–83 की ऐक्सैस डिमान्डज ओवर ग्रान्टस एंड ऐप्रोप्रिए ांज पर डि ाक ान होगी।

हाउस का टाईम सेब करने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई All the Demands for Grants for these years will be deemed to have been read and moved together.

आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर डि ाक ान कर सकते है लेकिन डि ाक ान स्टार्ट करने से पहले उस डिमान्ड का नम्बर और ईयर बता दें जिसको वे डि ाक्स करना चाहते है।

डि ाक ान के बाद हर साल डिमान्डज वोटिंग के लिए अलग अलग पुट की जायेंगी।

YEAR 1981-82

That a grant of a sum not exceeding Rs 1122514 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 2-General Administration.

That a grant of a sum not exceeding Rs 10747511 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 3-Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs 10388226 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 4-Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs 1325013 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 5-Excise and Taxation.

That a grant of a sum not exceeding Rs 19750653 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 6-Finance.

That a grant of a sum not exceeding Rs 2799313 be made to regularize the charges already incurred in excess of

the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 7-Other Administrative Services.

That a grant of a sum not exceeding Rs 52466169 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 8-Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs 460961 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 14-Food and Supplies.

That a grant of a sum not exceeding Rs 304029881 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 15-Irrigation.

That a grant of a sum not exceeding Rs 4197200 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 16-Industries.

That a grant of a sum not exceeding Rs 5222801 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 20-Forests.

That a grant of a sum not exceeding Rs 52395168 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 23-Transport.

YEAR 1982-83

That a grant of a sum not exceeding Rs 994950 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 2-General Administration.

That a grant of a sum not exceeding Rs 7932645 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 3-Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs 10015903 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 4-Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs 19325206 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 6-Finance.

That a grant of a sum not exceeding Rs 45544496 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 8-Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs 10704584 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 9-Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs 18120460 be made to regularize the charges already incurred in excess

of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 11-Urban Development.

That a grant of a sum not exceeding Rs 1211127 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a grant of a sum not exceeding Rs 946936 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 14-Food and Supplies.

That a grant of a sum not exceeding Rs 463255122 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 15-Irrigation.

That a grant of a sum not exceeding Rs 437817 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 17-Agriculture.

That a grant of a sum not exceeding Rs 13234700 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 20-Forests.

That a grant of a sum not exceeding Rs 7363338 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 21-Community Development.

That a grant of a sum not exceeding Rs 10834404 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 23-Transport.

That a grant of a sum not exceeding Rs 17544837 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 25-Loans & Advances.

चौधरी रो ान लाल आर्य (छछरौली): अध्यक्ष महोदय, मै डिमान्ड नम्बर तीन पर सब से पहले बोलना चाहूंगा। स्पीकर साहब, हाउस में चीफ मिनिस्टर तथा होम मिनिस्टर साहब विराजमान है। इनका ध्यान मै एक वि ोश बात की ओर दिलाना चाहता हूं। सभी को मालूम है कि पुलिस विभाग में कुछ कर्मचारी इतना बढिया काम करते हे जिसके लिए उन्हे राश्ट्रपति एवार्ड देने के लिए सिफारि ा की जानी चाहिए या सरकार की ओर से उन्हे सम्मानित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार का एक केस मै हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं। एक डी0 एस0 पी0 अम्बाला में तैनात है। वह सरकारी डियूटी पर जा रहा था। उसने रास्ते में देखा कि एक बस का ऐक्सीडैंट हो गया है। उस डी0 एस0 पी0 ने वहां जा कर सारी सवारियों को सम्भाला। उसकी वर्दी खुन से रंग गई। फिर उसने घायल सवारियों को हस्पताल मे दाखिल करवाया। अगर वह डी0 एस0 पी0 मौके पर न पहुंचता और उनको समय पर हस्पताल में दाखिल न करवाता तो उनमें से दो सवारियां तो मर जाती। उसकी भागदौड से उन्हे समय पर एड

मिली। इसलिए मै आपके जरिए सरकार से अनुरोध करुंगा कि जो कर्मचारी इतना अच्छा कार्य करने वाले है, उन्हे वि ोश पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि उनका उत्साह बढे। अच्छे आदमी की कदर की जानी चाहिए और गलत आदमी का दण्ड दिया जाना चाहिए, जिससे व्यवस्था ठीक चलती रहे।

अध्यक्ष महोदय, डिमान्ड नम्बर चार रैवेन्यू का बारे में है। रैवेन्यू डिपार्टमैंअ को जो पैसा दिया जा रहा है, उसके बारे में मै एक बात कहना चाहता हूं। पिछले दिनो हरियाणा में काफी ओले पडे थे। हमारे इलाके में और अम्बाला जिले के और हिस्सों में भी काफी ओले पडे थे। उन ओलो के कारण जिन लोगो की फसलो को नुक्सान पहूंचा, उन्हे राहत नही दी गई। अब पता नही हमारे ही जिले में नही पहुंची या हमारे ही हलके में नही पहुंची। मेरा कहने का मतलब है कि वहां राहत कार्य नही हुआ। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इस बात पर गौर किया जाये। सरकार को पता करना चाहिए, किस जिले को राहत कार्य पहुंचा है और किस को नही पहुंचा है।

डिमान्ड नम्बर 15 इरीगे ान के विशय में है। इस बारे में मै निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि हर किसान के खेत में टेल तक पानी पहूंचे। हमारे इरीगे ान एण्ड पावर मिनिस्टर साहब इस बात के बारे में इस महान सदन में बताने की कृपा करें कि कितना पैसा इसके लिए मंजूर किया गया है। वे किस किस इलाके में किसानो को पानी

देंगे, कुल कितना पानी देंगे और अगर वे हल्कावार यह ब्यौरा बताने की कृपा करेंगे, तो उनकी बडी मेहरबानी होगी। (घंटी) मै एक मिनट में खत्म करुंगा। हमारे यहां एक दादूपूर नलवी स्कीम बनी हुई है। यह हमारे इलाके की बडी इम्पोर्टैंट नहर है। कई सालो से रिवाज चला आ रहा है कि जब भी फाइनैंि ायल ईयर क्लोज होने का वक्त आता है तो उस समय सरकार बगैर खर्च किए पैसा छोड देती है और अगले साल फिर अलौट कर देती है। सदन में यह सरकार कहती है कि हम उस इलाके का बहुत भारी ख्याल रखते है। तीन साल से यह पैसा सरेंडर कर रहे है और अगली बार फिर अलाट कर देते है जैसे किसी के आगे मुली बांध दे तो वह इसी उम्मीद में चलता रहता है कि उसके मुहं में मूली आएगी लेकिन वह आती है नही। इसलिए मै निवेदन करुंगा कि इस अ योरैंस को लागू करने की कृपा करें ताकि वहां पर यह योजना पूरी हो सके।

अब मै इंडस्टरीज़ के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज भी हमारा इलाका पिछडा हुआ है। मेरा कहना यह है कि ऐसे इलाको में इंडस्टरीज लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये। इससे हमारी हरियाणा सरकार को भी लाभ होगा। इसके अलावा जो बेरोजगार नौजवान है, उनको भी रोजगार मिलेगा। मेरे हल्के में खास तौर पर कोई भी इंडस्टरी नही है। मै यह चाहूंगा कि जिस जिस क्षेत्र में जैनुइन मांग है, वहां पर इंडस्टरी लगनी चाहिए। इस बात के लिए एक कमेटी बना दी जाये जो वहां पर

जाकर देखें कि वहां पर मांग वाकई जैनूइन है या नही। इसका फैसला पक्षपातरहित आधार पर हो कि किस इलाके में इंडस्ट्री लगनी चाहिए।

अब मै फौरेस्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह बात ठीक है कि फोरेस्ट महकमा काफी दिनों से बडी भारी स्पीड से काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनो में तो कुछ ज्यादा ही स्पीड पकडी हुई है। इसमें हरिजनो के घरो के अन्दर पेड लगाने का उत्साह है। मै इनसे यह कहना चाहूंगा कि हरिजनो के घरों के अन्दर पेड लगाने की कृपा न करें, यदि वह बाहर ही सडको के किनारे या दूसरी जगहो पर लगाये ंतो बडी मेहरबानी होगी। हमारे इलाके में फौरैस्ट डिपार्टमैंट की बडी मेहरबानी है। ये जितनी ज्यादा मेहरबानी करते है उतनी ज्यादा गडबड करते हैं। अगर ऐसा करने से सरकार उनको रोक दे तो बडी मेहरबानी होगी।

ट्रांसपोर्ट के बारे में भी मै कुछ निवेदन करना चाहूंगा। इसके बारे में मैने कल भी निवेदन किया था। मै एक बात अव य ही कहना चाहता हूं कि टरांस्पोर्ट डिपार्टमैंट एक बहुत ही बडा जनसम्पर्क माध्यम है। आज सुबह ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महोदय ने यह बताया है कि कितने लोग रोजाना सफर करते है और हमारी बसें कितने किलामीटर रोज चलती है। कितने ही लोग हमारी रोडवेज के माध्यम से हमारे सम्पर्क में आते हैं। सरकार की छवि बनाने के रोडवेज एक अहम माध्यम है। जहां इस महकमे की पैसी की मंजूरी के लिए मांग है और इस पैसे को खर्च करने के लिए

मंजूरी दी जा रही है, वहां इसको लोगो की जरुरतों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हम रोज देखते है कि बस स्टेंड पर लोगो को पीने के लिए पानी नही होता। बस स्टैण्ड पर गन्दगी होती है। कोई इस तरफ ध्यान नही दिया जाता। मंत्रीगण तो कारों मे निकल जाते है। बसों मे सफर करने का उनको मौका ही नही मिलता। बस–स्टैण्डज़ पर तो सिर्फ उदघाटन के समय ही जाते है। उस समय तो भाायद सफाई बहुत अच्छी होती है। तो मेरा कहना यह है कि आम तौर पर बस–स्टैण्डज का बहुत बुरा हाल है। इनके सुधार से सरकार की इमेज बनेगी। सरकार का फर्ज है कि वह जिन लोगों से टैक्स लेकर चलती है उनका कुछ ख्याल भी रखें। इन भाब्दों के साथ ही मैं अपनी बातें कहते हुए अपना स्थान लेता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि इन डिमांडज को पास कर दिया जायं। धन्यवाद।

वित्त मंत्री (चौधरी कटार सिंह छोकर): स्पीकर साहब, यह खर्चा तो हो चुका है, इस पास कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: अब मै ईयर 1981–82 की वेरियस डिमांडज हाउस में वोटिंग के लिए रखूंगा।

Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs 1122514 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 2-General Administration.

That a grant of a sum not exceeding Rs 10747511 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 3-Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs 10388226 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 4-Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs 1325013 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 5-Excise and Taxation.

That a grant of a sum not exceeding Rs 19750653 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 6-Finance.

That a grant of a sum not exceeding Rs 2799313 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 7-Other Administrative Services.

That a grant of a sum not exceeding Rs 52466169 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 8-Buildings and Roads.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs 460961 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 14-Food and Supplies.

That a grant of a sum not exceeding Rs 304029881 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 15-Irrigation.

That a grant of a sum not exceeding Rs 4197200 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 16-Industries.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs 5222801 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 20-Forests.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs 52395168 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1981-82 in respect of 23-Transport.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब मै ईयर 1982–83 की वेरियस डिमांडज हाउस में वोटिंग के लिए रखूंगा।

Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs 994950 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 2-General Administration.

That a grant of a sum not exceeding Rs 7932645 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 3-Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs 10015903 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 4-Revenue.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs 19325206 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 6-Finance.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs 45544496 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 8-Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs 10704584 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 9-Education.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs 18120460 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 11-Urban Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs 1211127 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 13-Social Welfare and Rehabilitation.

That a grant of a sum not exceeding Rs 946936 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 14-Food and Supplies.

That a grant of a sum not exceeding Rs 463255122 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 15-Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs 437817 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 17-Agriculture.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs 13234700 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 20-Forests.

That a grant of a sum not exceeding Rs 7363338 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 21-Community Development.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs 10834404 be made to regularize the charges already incurred in excess

of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 23-Transport.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a grant of a sum not exceeding Rs 17544837 be made to regularize the charges already incurred in excess of the grans voted by the Legislative Assembly for the year 1982-83 in respect of 25-Loans & Advances.

The motion was carried.

वर्श 1986–87 के सप्लीमैंटरी ऐस्टीमैटस (दूसरी किस्त) पर चर्चा तथा अनुदान

(1) राज्य के राजस्वों पर प्रभारित अनुमानो पर चर्चा।

(2) अनुपूरक अनुदानों की मांगो पर चर्चा तथा मतदान।

श्री अध्यक्षः अब ईयर 1986–87 के सप्लीमैंटरी ऐस्टीमैटस (सैकिण्ड इन्सटालमैंट) पर डिस्क ान होगी। पहली प्रैक्टिस के मुताबिक और हाउस का टाईम सेव करने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गयी all demands will be deemed to have been read and moved. अगर कोई मैम्बर बोलना चाहे तो वह बोलने से पहले उस डिमांड का नम्बर बता दे। डिस्क ान के बाद डिमांडज हाउस की वोट के लिए पुट की जाएंगी।

That a supplementary sum not exceeding Rs. **485000** for revenue expenditure be granted to the Governor to

defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 1- Vidhan Sabha**.

That a supplementary sum not exceeding Rs. **15402000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 2- General Administration**.

That a supplementary sum not exceeding Rs. **43302000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 3- Home**.

That a supplementary sum not exceeding Rs. **43382000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 4- Revenue**.

That a supplementary sum not exceeding Rs. **4512000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 5- Excise and Taxation.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **2040000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 6- Finance.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **1730600** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 7-Other Administrative Services.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **23254000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 8-Buildings and Roads.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **128244000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 9-Education.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **41673000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 10-Medical and Public Health.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **1172500** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 11-Urban Development.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **36508450** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **2911000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 14-Food and Supplies.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **40279000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 15-Irrigation.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **4342590** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 16-Industries.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **43750000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 17-Agriculture.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **60870000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 21-Comminity Development.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **40278000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 23-Transport.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **800917000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 25-Loans and Advances.**

(No Member rose to speak)

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. **485000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 1-Vidhan Sabha**.

That a supplementary sum not exceeding Rs. **15402000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 2-General Administration**.

That a supplementary sum not exceeding Rs. **43302000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 3-Home**.

That a supplementary sum not exceeding Rs. **43382000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 4- Revenue**.

That a supplementary sum not exceeding Rs. **4512000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 5- Excise and Taxation.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **2040000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 6- Finance.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **1730600** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 7- Other Administrative Services.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **23254000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 8- Buildings and Roads.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **128244000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of

payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 9-Education.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **41673000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 10-Medical and Public Health.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **1172500** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 11-Urban Development.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. **36508450** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 13-Social Welfare and Rehabilitation.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **2911000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 14-Food and Supplies.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **40279000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for

the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 15-Irrigation.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **4342590** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 16-Industries.**

That a supplementary sum not exceeding Rs. **43750000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 17-Agriculture.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. **60870000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 21-Comminity Development.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. **40278000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 23-Transport.**

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is-

That a supplementary sum not exceeding Rs. **800917000** for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year ending 31st March] 1987 in respect of Demand **No. 25-Loans and Advances.**

The motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब हाउस मन्डे, दि सैकेन्ड मार्च, 1987 बाद दोपहर 2.00 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

12:37 बजे

(तत्प चात सदन सोमवार, दिनांक 2 मार्च, 1987 को बाद दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)